● वर्ष-2
● अंक-248
रायपुर, गुरुवार
08 जून 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

मध्यप्रदेश में कांग्रेस का माइंड गेम

भाजपा-संघ के सर्वे पर पार्टी ने तैयार की चुनावी रणनीति

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ वक्त बचा है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनावी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आरएसएस के सर्वे से भाजपा में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। जबकि पार्टी और आरएसएस के विभिन्न सर्वे में पार्टी को 60 से भी कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।

हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्यप्रदेश में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कई सर्वे सामने आए हैं, जिनमें प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। साथ ही भाजपा 55 सीटों से भी कम पर सिमट रही है। कांग्रेस के पास 2018 के अपने 15 महीनों का कार्यकाल और कमलनाथ जैसे निर्विवाद और अनुभवी नेता का साथ है। इसे लेकर वह जनता के बीच पहुंच रही है।

दरअसल, मध्यप्रदेश में भाजपा पर 18 वर्षों की देनदारियां और सरकार की कई ऐसी अधूरी घोषणाएं हैं, जो गंभीर सत्ता विरोधी लहर (एंटी इनकम्बेंसी) का रूप ले चुकी है। पिछले 5 महीनों में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर छह अलग-अलग सर्वे सामने आए हैं। सभी सर्वे में भाजपा की सीटें लगातार घटती जा रही हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के सर्वे में भी पार्टी बुरी तरह से हारती हुई दिख रही है। ये सर्वे आने के बाद से मध्यप्रदेश भाजपा में खलबली मची है और ये सुझाव भी मिला है कि 60 फीसदी भाजपा विधायकों के टिकट काटे जाएं।

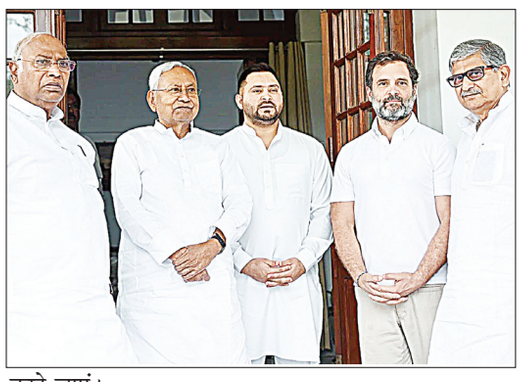

कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के जीत के दावे के कई कारण है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी देने वाली कांग्रेस अब पूरे जोश से मैदान में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कहते हैं कि 2018 के चुनाव से पहले मई में प्रदेश अध्यक्ष बना था, नवंबर में चुनाव थे। मध्यप्रदेश में काफी लोग मुझे पहचानते नहीं थे, मेरी कार्यशैली से वाकिफ नहीं थे, परंतु आज ऐसा नहीं है। मध्यप्रदेश का हर वर्ग कमलनाथ को और कमलनाथ की कार्यशैली को जानता और पहचानता है। वरिष्ठ पत्रकार ऋषि पांडेय कहते हैं कि अभी तक की स्थिति में कांग्रेस भाजपा से आगे नजर आ रही है। पार्टी इस तरह के सर्वे सामने लाकर मध्यप्रदेश के लोगों के मन की स्थिति को टटोलने का प्रयास कर रही है। क्योंकि इससे पहले के आप कई चुनाव देख लें, कांग्रेस कभी इतनी एक्टिव और आक्रमक नहीं होती थी, जितनी इस बार नजर आ रही है। कमलनाथ सीधे भाजपा सरकार और प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। कमलनाथ ने भी महिलाओं से वादा किया है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार आती है, तो नारी सम्मान योजना को लागू किया जाएगा। इसके फॉर्म अभी से भरे जाने लगे हैं। इसके जरिए पार्टी लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करने के पूरे जतन कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह भी पूरे प्रदेश में इन दिनों भ्रमण कर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। वे खुले मंच से कह रहे हैं कि गुटबाजी हमें खत्म करना और साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। क्योंकि यह चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति वाला है।

प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत के बाद प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। कार्यकर्ता पहले से ज्यादा उत्साह में हैं। हिमाचल और कर्नाटक चुनाव के बाद पार्टी ये समझ रही है कि राज्यों के चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश की जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाते हुए दिख रही है। चाहे वह भ्रष्टाचार का मामला हो या कर्मचारियों की मांगों का सभी को प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है।

23 जून को होगी विपक्ष की बैठक

12 जून को प्रस्तावित बैठक कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी की दूरी के कारण टालनी पड़ी थी, लेकिन अब जनता दल यूनाईटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा की है कि विपक्षी दलों के तमाम प्रमुख नेता 23 जून को पटना में जुटेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ बुधवार शाम प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राकांपा प्रमुख व पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाकपा महासचिव डी राजा, वरिष्ठ वामपंथी नेता सीताराम येचुरी और दीपांकर भट्टाचार्य ने भी 23 जून को पटना में विपक्षी एकता के लिए होने वाली बैठक में आने की स्वीकृति दी है।

12 जून की बैठक टलने पर नीतीश थे नाराज

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के कई नेताओं से मुलाकातों के बाद 12 जून को पटना में बैठक रखी थी। लेकिन, जब उन्हें यह पक्का हुआ कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी इस बैठक में नहीं आ रहे हैं तो आननफानन में इस बैठक को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्षी दलों की बैठक में पार्टी अध्यक्षों को आना है और अगर कांग्रेस की ओर से ही इसकी अस्पष्टता रहेगी तो गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा था कि जल्द ही कांग्रेस के साथ बात कर अगली तारीख बताई जाएगी। बुधवार को जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कांग्रेस समेत तमाम प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं का नाम गिनाते हुए जानकारी दी कि 23 जून को पटना में ही बैठक होगी।

इन दिनों ✍ शशांक द्विवेदी

कैसे रुकेंगे भीषण रेल हादसे?

ओडिशा के बालासोर जिले में हुए भीषण रेल हादसे के बाद संभावित परिचालन खामियों के बारे में सवाल उठने लगे हैं। इतने बड़े रेल हादसे को तकनीकी खराबी या मानवीय भूल, क्या माना जाए? वैसे तो इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और इस घटना के पीछे साजिश के भी संकेत मिल रहे हैं। फिर भी दुर्घटना को लेकर उठ रहे सवालों में एक सवाल ये भी है कि कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस मालगाड़ी के ट्रैक पर कैसे आ गई। एक तरफ देश बुलेट ट्रेन के सपने देख रहा है वहीं दूसरी तरफ भीषण रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस भीषण रेल हादसे के बाद अब एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसे हादसों के लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा देश में वह दिन कब आएगा जब यह सुनिश्चित होगा कि रेलयात्रा करने वाले यात्री अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचेंगे। दरअसल रेल दुर्घटना का असर बाकी किसी भी हादसे से कई गुना ज्यादा होता है। इसका सीधा कारण यात्रियों की संख्या है। भारत में अंतर्देशीय परिवहन के लिए रेल सबसे बड़ा माध्यम है। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक भारत में हर रोज सवा दो करोड़ से भी ज्यादा यात्री सफर करते हैं जबकि 87 लाख टन के आसपास सामान ढोया जाता है साथ ही कुल 67415 किलोमीटर के ट्रैक पर जरा-सी गफलत लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाल सकती है। ट्रेन हादसे के बाद एक बार फिर से रेलयात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हादसे की खबरों के बीच भारतीय रेलवे के उस %कवच% की चर्चा हो रही है, जो अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में लगा होता तो इतना बड़ा रेल हादसा न हुआ होता। रेलवे के 'कवच' का उद्घाटन पिछले साल हुआ था। दरअसल रेलवे ने अपने पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए %कवच% का निर्माण करवाया था जिसके अस्तित्व में आने के बाद ये माना जा रहा था कि भविष्य में ट्रेन हादसों पर एक दिन जरूर लगाम लग जाएगी। 'कवच' के सफल परीक्षण के बाद उसे रेलवे का मास्टर स्ट्रोक और बड़ी क्रांति माना जा रहा था। इस तकनीक में रेलवे वो तकनीक विकसित कर चुका है जिसमें अगर एक ही पटरी पर ट्रेन आमने सामने भी आ जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। रेल मंत्रालय ने तब बताया था कि इस 'कवच' टेक्नोलॉजी को धीरे-धीरे देश के सभी रेलवे ट्रैक और ट्रेनों पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब रेलवे के इन्हीं दावों पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल मार्च 2022 में हुए कवच टेक्नोलॉजी के ट्रायल में एक ही पटरी पर दौड़ रही दो ट्रेनों में से एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे और दूसरी ट्रेन के इंजन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन खुद मौजूद थे। एक ही पटरी पर आमने सामने आ रहे ट्रेन और इंजन 'कवच' टेक्नोलॉजी के कारण टकराए नहीं, क्योंकि कवच ने रेल मंत्री की ट्रेन को सामने आ रहे इंजन से 380 मीटर दूर ही रोक दिया और इस तरह परीक्षण सफल रहा। कवच टेक्नोलॉजी को देश के तीन वेंडर्स के साथ मिलकर आरडीएसओ (रिसर्च डिजाइन एंड स्टेंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन) ने डेवलप किया था ताकि पटरी पर दौड़ती ट्रेनों की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। पिछले साल कवच के सफल परीक्षण के बावजूद इसको पुरे देश में रेल नेटवर्क पर लागू करना चाहिए था लेकिन रेलवे ने इस पर ठीक से काम नहीं किया। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्दी ही कवच प्रणाली से लैस करना होगा।

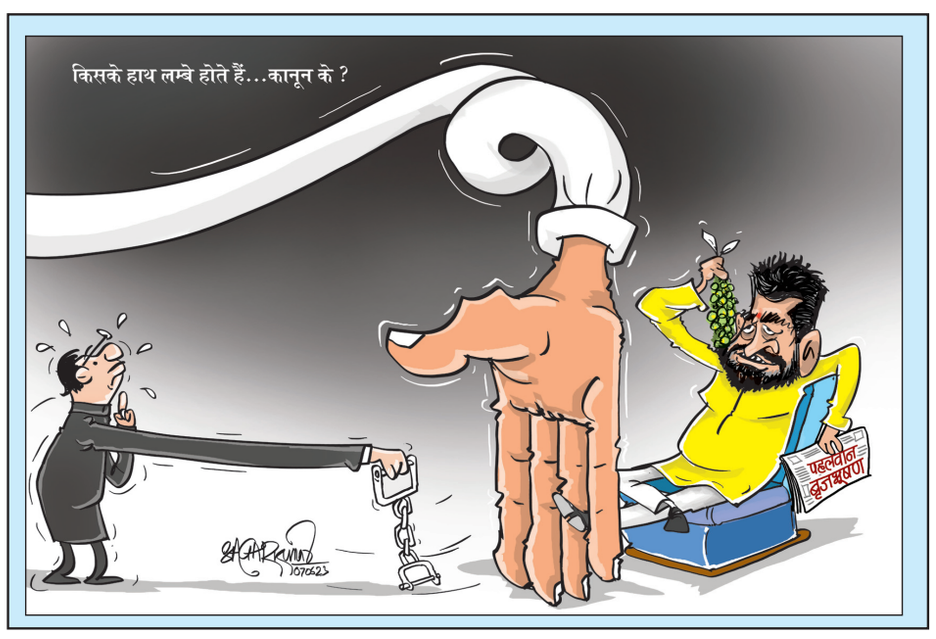

उत्तराखंड के मंदिरों में जाने के लिए ड्रेस कोड

देहरादून। मंदिर में जाकर भगवन दर्शन करना है तो इसके लिए अब तक जहां श्रद्धा और भक्ति सबसे अहम मानी जाती थी। वहीं अब पर्याप्त ड्रेस कोड भी होना आवश्यक है। ऐसा आदेश हाल ही में उत्तराखंड में लागू किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जिलों में मंदिर में प्रवेश करने से पहले उचित वस्त्र पहनने वालों को ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा जबकि जिन श्रद्धालुओं ने उचित पोशाक धारण नहीं की होगी उनके मंदिर में जाने पर प्रतिबंध होगा।

शुरुआत में ये आदेश हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर, देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में लागू किया गया है। इस संबंध में महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा के सचिव महंत रविन्द पुरी ने रविवार को कहा कि दक्ष प्रजापति मंदिर (हरिद्वार), टपकेश्वर महादेव मंदिर (देहरादून) और नीलकंठ महादेव मंदिर (ऋषिकेश) में "छोटे कपड़े पहने महिलाओं/पुरुषों" के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पुरी ने कहा कि ऐसी महिलाओं को ही मंदिरों में प्रवेश की अनुमति होगी जिन्होंने 80 प्रतिशत तक शरीर ढंकने वाले कपड़े पहने हों। उन्होंने कहा कि महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा से जुड़े इन मंदिरों में यह प्रतिबंध तत्काल प्रभावी होगा। महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा दशनाम नागा संतों से संबंधित है। पुरी ने कहा कि जल्दी ही यह प्रतिबंध देश भर में अखाड़े से जुड़े मंदिरों में लागू किया जाएगा। प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता के संबंध में प्रश्न करने पर पुरी ने कहा, "कभी-कभी, मंदिर आने वाले व्यक्तियों के कपड़े इतने छोटे होते हैं कि दूसरे लोगों को उन्हें देखकर शर्म आती है।"

उन्होंने कहा, "हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर- जिसे दक्ष प्रजापति मंदिर भी कहा जाता है, को भगवान शिव का ससुराल माना जाता है। दुनिया भर के लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं।" पुरी ने कहा, "प्रत्येक सोमवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। आज के युवा, मंदिरों में ऐसे कपड़े पहन कर आते हैं जो शुचिता के प्रति उनकी उपेक्षा को दर्शाता है।" उन्होंने कहा कि ऐसे वस्त्रों से "श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है" और वे अकसर मंदिर समिति से इसकी शिकायत करते हैं।

प्रमुख समाचार

वैक्सीन-दवाई बनाने में भारत की क्षमता को जी20 ने माना

हैदराबाद। जी20 के तीसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में कोविड के दौरान भारत की भूमिका को सराहा गया। इस बैठक में क्लाइमेट चेंज और सेहत पर इसके प्रभाव पर भी चर्चा हुई। बैठक में बैक्टीरिया और वायरस के प्रति रजिस्टेंस का भी जिक्र हुआ। कोविड का जिक्र कर विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट जेरेमी फर्रार ने कहा कि तीन वर्षों के कठिन समय में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वैक्सीन, दवाएं बनाने की दिशा में भारत वैश्विक स्तर पर अगुआई कर रहा है। मेडिकल जांच (डायग्नोस्टिक) के क्षेत्र में नई तकनीक दूसरे देशों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही हैं। जी20 बैठक में प्रमुख अजेंडा यह रहा कि डिजिटल हेल्थ कैसे दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचे और इस क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका है। भारत की अगुआई से दुनिया को बड़ी उम्मीद है।

सांप्रदायिक मतभेदों के कारण हुई हिंसा: किरेन रिजिजू

इंफाल। मणिपुर में एक महीने पहले भड़की जातीय हिंसा में कम से कम 98 लोगों की जान जा चुकी है और 310 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राज्य में फिलहाल कुल 37,450 लोगों ने 272 राहत शिविरों में शरण ले रखी है। मणिपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, सांप्रदायिक मतभेदों के कारण हिंसा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद 4 दिनों तक यहां रहे और एसओयू समूहों से यथास्थिति बनाए रखने की अपील की और कई ने आत्मसमर्पण भी किया। रिजिजू ने कहा कि यह एक सतत समस्या है और गृह मंत्री ने स्वयं इसका जमीनी मूल्यांकन किया और उन्होंने पहले शांति स्थापित करने के लिए शांति प्रस्ताव दिया, फिर जो भी मांग होगी, जो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर के काकचिंग जिले में सेरौ इलाके में मंगलवार सुबह विद्रोहियों के साथ गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एक

रूस में फंसे यात्रियों के लिए एअर इंडिया का विमान रवाना

नई दिल्ली। उड़ान में तकनीकी खामी के कारण रूस में फंसे 216 यात्रियों को अमेरिका में उनके गंतव्य सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचाने के लिए एअर इंडिया का एक विमान बुधवार अपराह्न तीन बजकर 20 मिनट पर मुंबई से मगदान (रूस) रवाना हुआ। विमानन कंपनी ने कहा कि विमान मगदान में फंसे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर आठ जून को सैन फ्रांसिस्को की उड़ान भरेगा। एअर इंडिया की उड़ान संख्या एइआई-173 छह जून को दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुई थी लेकिन बीच हवा में बोइंग-777 विमान के एक इंजन में तकनीकी खराबी आने का पता चला। इस विमान को रूस के मगदान हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरना पड़ा था। इस विमान में 216 यात्री और चालक दल के 16 सदस्य सवार थे। सैन फ्रांसिस्को ले जाने वाले विमान को पहले बुधवार को दोपहर एक बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मगदान के लिए उड़ान भरनी थी।

सरकार ने 15 जून तक मांगा समय-बजरंग पुनिया

नई दिल्ली। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और सत्यव्रत कादियान नई दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर उनसे बातचीत की है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की लंबी बैठक खत्म हो चुकी है। यह बैठक लगभग पांच घंटे तक चली है। गतिरोध खत्म करने के लिए ठाकुर ने यह बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद बजरंग पुनिया ने कहा कि कुछ मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच 15 जून तक पूरी हो जानी चाहिए और मंत्री जी ने हमसे तब तक विरोध प्रदर्शन नहीं करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला पहलवानों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा।

मुख्तार अंसारी का करीबी संजीव जीवा की हत्या

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आई है। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था। दावा किया जा रहा है कि कातिल वकील की ड्रेस पहनकर आए थे। उन्होंने कचहरी में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। मारा गया संजीव जीवा माहेश्वरी भी उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया था। संजीव जीवा पर भाजपा नेता ब्रह्मदत्त दिवेदी के हत्या का आरोप था। संजीव जीवा पर उस समय हमला किया गया जब उसे एक आपराधिक मामले में अदालत में सुनवाई के लिए लाया जा रहा था। टीवी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बदमाशों ने कथित तौर पर 6 राउंड गोलियां बरसाईं। गैंगस्टर संजीव जीवा को कुख्यात गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। संजीव जीवा की हत्या करने के बाद हमलावर मौके से फरार होने में सफल रहे।

सात बार अमेरिका जा चुके पीएम मोदी की पहली राजकीय यात्रा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। नौ साल में आठवीं बार अमेरिका दौरे पर जा रहे मोदी की यह पहली राजकीय यात्रा है। इस दौरान मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडन के मेहमान होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान 350 फाइटर जेट इंजनों के भारत में निर्माण का बड़ा रणनीतिक सौदा हो सकता है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जनरल इलेक्ट्रिक को भारत में फाइटर जेट इंजन बनाने का परमिट देने के समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यह सरकार से सरकार का समझौता होगा। व्यापार परिषद की एयरोस्पेस व रक्षा समिति दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र के उत्पादकों को करीब लाने के लिए इंडस एक्स का आयोजन करेगी। इसके अलावा 30 रूक्त-9 क्वआर्म्ड ड्रोन खरीदने का समझौता भी पीएम की इस यात्रा में हो सकता है। यह समझौता करीब 22 हजार करोड़ रुपए का होगा। समझौते होने पर ऐसे 10 ड्रोन तीनों सेनाओं को मिलेंगे। ये ड्रोन लगातार 48 घंटे तक उड़ान भरते हुए 6,000 किलोमीटर तक की रेंज में ऑपरेशन कर सकते हैं।

राजकीय यात्रा में क्या-क्या होता है?

अपनी मेजबानी में मेजबान देश संबंधित अतिथि के स्वागत में कई कार्यक्रमों का आयोजन करता है। राजकीय अतिथि को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। मिलिट्री बैंड द्वारा दोनों देशों का राष्ट्र गान बजाया जाता है। राजकीय अतिथि और मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष के बीच उपहारों का आदान-प्रदान भी होता है। राजकीय अतिथि के सम्मान में राजकीय भोज का भी आयोजन होता है।

राजकीय यात्रा क्यों अहम होती है?

किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा द्वारा जब किसी दूसरे देश का आधिकारिक दौरा किया जाता है तो उसे राजकीय यात्रा कहते हैं। इस तरह के दौरे में संबंधित राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राजा को उस देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा राजकीय यात्रा के लिए न्योता दिया जाता है, जहां की वह यात्रा करने वाला है। इस तरह की यात्रा का सारा खर्च मेजबान देश उठाता है। इसके साथ ही मेजबान देश अपने आगंतुकों के लिए उच्चतम स्तर के आतिथ्य का प्रबंध करता है।

अमेरिका में उच्चाधिकारियों की कितनी तरह की यात्राएं होती हैं?

अमेरिका की बात करें तो यहां का दौरा करने वाले उच्चाधिकारियों के लिए कुल पांच तरह के दौरे तय किए गए हैं। इन्हें राजकीय यात्रा, आधिकारिक यात्रा, आधिकारिक कार्य यात्रा, कार्य यात्रा और निजी यात्रा कहा जाता है। इनमें राजकीय यात्रा सबसे ऊपर है। इसका न्योता केवल अमेरिकी राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। हर यात्रा का प्रोटोकॉल अलग होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक गेस्ट हाउस ब्लेर हाउस है। यह गेस्ट हाउस व्हाइट हाउस के पास बना है। अमेरिका के राजकीय अतिथि को इसी में ठहराया जाता है। राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। इसके साथ ही मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में राजकीय भोज (लंच) भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी से पहले अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे। प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह की यह राजकीय यात्रा 23 से 25 नवंबर 2009 के बीच हुई थी।

प्रधानमंत्री मोदी तो पहले भी कई बार अमेरिका जा चुके हैं उन दौरों का क्या?

बीते नौ साल में प्रधानमंत्री मोदी सात बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। इनमें से कोई भी राजकीय दौरा नहीं था। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 25 सितंबर से एक अक्तूबर 2014 तक प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए। यह दौरा कार्य यात्रा श्रेणी में शामिल था। 25 से 29 सितंबर 2015 के दौरान मोदी ने आयरलैंड और अमेरिका दौरा किया। इस दौरे में मोदी संयुक्त राष्ट्र आम सभा में शामिल होने अमेरिका गए थे। 30 मार्च से तीन अप्रैल 2016 के दौरान प्रधानमंत्री ने बेल्जियम, अमेरिका और सऊदी अरब के दौरे पर रहे। दो महीने बाद ही चार से नौ जून 2016 तक मोदी ने अमेरिका समेत पांच देशों की यात्रा की।

नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे पांच वाहनों में की आगजनी

कांकेर। पखांजूर क्षेत्र के छोटेबेटिया थाना क्षेत्र अंर्गत ग्राम सितरम के आसपास सड़क निर्माण कार्य में लगे कुछ वाहनों को नक्सलियों ने आग लगा दिया है। बताया जाता है कि आगजनी में 5 वाहनें जलकर नष्ट हो गई है।

सूत्रों ने बताया कि नगर के आसपास नक्सलियों ने एक बार फिर से अपना आतंक बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस बार नक्सलियों ने छोटेबेटिया थाना क्षेत्र के ग्राम सितरम के आसपास सड़क निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों में आगजनी की है। नक्सलियों ने 5 गाड़ियों में आग लगाई है, इसमें 2 ट्रक, 1 पोकलेन, 1 रोड रोलर, 1 पानी टैंकर शामिल है। सभी गाड़ियां राजमुंडा से कोपेंनगुंडा में चल रहे सड़क निर्माण में लगी थी। पखांजूर एसडीओपी के अनुसार करीब 5 गाड़ियों में आगजनी की सूचना मिली है। अंदरुनी क्षेत्र होने के कारण ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आ रही हैद्ध हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब

नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, नक्सली सड़क निर्माण कार्य का विरोध करने के लिए आए दिन वाहनों में आगजनी करते हैं।

कोबरा बटालियन-नक्सलियों के बीच मुठभेड़

बीजापुर। प्रदेश के बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना आ रही है। बताया जाता है कि दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। यह मुठभेड़ कोबरा बटालियन और नक्सलियों के बीच हुई है। इसके अलावा बैकअप के लिए एसटीएफ के कमांडो पर पहुंच गए हैं। बताया जाता है कि कोबरा बटालियन के जवान बीजापुर और सुकमा जिले की सीमावर्ती इलाके में सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए हमले के बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पिछले 2 घंटे से यह मुठभेड़ जारी है। बताया जाता है कि हमले की सूचना मिलते ही एसटीएफ के कमांडो पर कोबरा जवानों की मदद के लिए मौके पर पहुंच गए हैं।

जवानों ने नक्सलियों के तीन मददगार को गिरफ्तार किया

जगदलपुर। छत्तीसगढ़-तेलंगाना राज्य की सीमा पर तेलंगाना राज्य की चेरला पुलिस, भद्राद्री कोठागुडेम स्पेशल पार्टी पुलिस और 141 बटालियन के जवानों ने संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग के तहत देवनगरम के पास नक्सलियों के लिए कोरियर का काम करने वाले तीन आरोपितों को विस्फोटक सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में पुनेम नागेश्वर राव, पुत्र बाबर राव (31) देवनगरम, देवासुरी मल्लिकार्जुनराव पुत्र शंकर राव (40) निवासी उंजुपल्ली दोनों चेरला जिले के हैं व एक अन्य वैलेपोगुलु उमाशंकर, पुत्र लक्ष्मैया (43) छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पामेड़ के अंबेडकर पारा का है। पुलिस ने नक्सली नेताओं के आदेश पर विस्फोटक सप्लाई करने जा रहे एक ड्रोन और एक खराद मशीन को पकड़ा है। जब्त सामान में 10 जिलेटिन स्टिक, 160 मीटर कॉर्डेक्स तार, 5 विद्युत डेटोनेटर, एक ड्रोन, लेथ मशीन है। तेलंगाना पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तीनों आरोपित प्रतिबंधित भाकपा-माओवादी की पमेदू एरिया कमेटी के लिए पिछले एक साल से कोरियर का काम कर रहे थे। नक्सलियों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करते थे। नक्सली नेताओं के आदेश पर चार माह पूर्व विजयवाड़ा से ड्रिलिंग मशीन खरीद कर सप्लाई की थी।

सिंचाई सुविधा को सदृढ़ करना सुनिश्चत करें अधिकारी : आकांक्षी जिला प्रभारी

कोरबा। नदी व नालों में बने एनीकट और व्यपवर्तन के माध्यम से जल संसाधन के अधिकारी सिंचाई सुविधा को विस्तार देना अधिकारी सुनिश्चत करें। योजना से क्षेत्र के किसानों को सिचाई हेतु और आवश्यकतानुसार लोगों को पेयजल के लिए पानी उपलब्धता की दिशा में ठोस कार्य की जानी चाहिए।

यह बात भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय डीओपीटी में संयुक्त सचिव एवं आकांक्षी जिला कोरबा के प्रभारी रजत कुमार ने मंगलवार को जटांगपुर एनीकट निरीक्षण के दौरान कही। उन्होने कटघोरा के आमाखोखरा व्यपवर्तन योजना का अवलोकन किया। यहां नहर निर्माण के लिए चल रहे कार्यो के गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जटांगपुर एनीकट में गेट का नियमित मेंटनेंस कराने, जलक्षेत्र में पानी की साफसफाई कराने कहा। संयुक्त सचिव ने आमाखोखरा में कटघोरा व्यपवर्तन का भी अवलोकन किया इस दौरान कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा एवं जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता पीके वासनिक, एसएल द्विवेदी, सब इंजीनियर, जिला पंचायत के कर्मचारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि जटांगपुर एनीकट योजना की प्रशासकीय स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, रायपुर द्वारा की प्रदान की गई थी। योजना का निर्माण औद्योगिक प्रयोजना हेतु किया गया है। योजना से कुल 25 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के माध्यम से लिफ्ट द्वारा सिंचाई प्रस्तावित है। वर्तमान में किसानो द्वारा कुल 25 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के माध्यम से लिफ्ट द्वारा सिंचाई किया जा रहा है। एनीकट का

जल भराव क्षमता 0.65 मिघमी है। एनीकट का अधिकतम जल भराव क्षेत्र 12.00 हेक्टेयर है। इसी तरह कटघोरा व्यपवर्तन योजना की प्रशासकीय स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, रायपुर द्वारा प्रदान की गई थी। इस योजना से 1991 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। कटघोरा नगर पालिका परिषद को पेयजल हेतु 1 32 मिलियन घन मीटर वार्षिक जल प्रदाय करना प्रस्तावित है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद कटघोरा को जल प्रदाय किया जा रहा है। बांध का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नहर का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस नहर के निर्माण होने से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के 24 ग्रामों में 1991 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिससे इनके आय में वृद्धि होने के साथ जीवन में खुशहाली आएगी।

जलशक्ति केंद्र का किया अवलोकन

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं आकांक्षी जिला कोरबा के प्रभारी रजत कुमार ने जिला पंचायत भवन में संचालित जलशक्ति केंद्र का अवलोकन किया और यहां की गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर संजीव कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक उदय किरण उपस्थित थे।

गेवरा विस्तार की जनसुनवाई आयोजित डंडे की जोर पर ग्रामीणों को कराया शांत

कोरबा। साउथ इस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड एसईसीएल गेवरा परियोजना की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न संगठन के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर विरोध दर्ज कराया और अधिकारियों पर वादाखिलाफी, नौकरी नहीं देने समेत कई आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। पुलिस व सुरक्षा कर्मियों ने ग्रामीणों को डंडे के बल पर शांत कर दिया और जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली। इस दौरान 75 लोगों लिखित व 55 ने मौखिक रूप से आपत्ति सुझाव दर्ज कराया।

एसईसीएल गेवरा परियोजना की उत्पादन क्षमता 700 लाख टन बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए मंगलवार को गेवरा इंदिरा स्टेडियम में पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की गई। मंच पर अपर कलेक्टर वीरेंद्र पाटले व पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेष पिस्दा, एसडीएम सीमा पात्रे, कौशल तेंदुलकर की उपस्थिति में प्रक्रिया शुरु हुई। जनसुनवाई का क्षेत्रवासी लगातार विरोध करते हुए स्थगित करने की मांग कर रहे थे। इसलिए एसईसीएल प्रबंधन की पहल पर काफी संख्या में पुलिस बल को स्टेडियम पहुंच मार्ग में डंडे के साथ तैनात कर दिया गया थाए ताकि सुनवाई के दौरान विरोध करने वाले स्थल पर न पहुंच सके। ग्रामीण जब कार्यक्रम स्थल पर झंडा बैनर लेकर जाने लगे, तब मार्ग में उपस्थित पुलिस व सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें रोकने का जबरन प्रयास किया गया।

इससे धक्कामुक्की व झूमा झटकी हुई, पर आक्रोशित रैली के रूप में आखिरकार स्थल पर पहुंचने सफल हो गए और जमकर स्थल पर नारेबाजी की। तब स्थल प उपस्थित पुलिस ने उन्हें डंडा से धक्का मार कर बाहर कर दिया। एसईसीएल के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों का कहना था कि जमीन अधिग्रहण के समय बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, पर नौकरी, मुआवजा, बसाहट देने में टालमटोल की नीति अपनाई जाती है। वर्षो से

रोजगार के प्रकरण लंबित रखे हैं और अभी भी अधिकारी प्रभावितों के साथ भेदभाव की नीति अपना रहे हैं। सुनवाई के दौरान अधिकांश लोगों ने खदान विस्तार का विरोध जताया, जबकि नाममात्र के लोग ही पक्ष में बोलने सामने आए। उनमें अधिकांश लोग एसईसीएल से जुड़े हुए थे। इस दौरान एसईसीएल के अधिकारी समेत काफी संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहा। जनसुनवाई में खदान में समाहित होने वाले सभी गांव के प्रभावितों को उपस्थिति होनी चाहिए और इस दौरान ग्रामीणों को प्रमुखता से बात रखने का अवसर मिलना चाहिए, पर गेवरा में हुई जनसुनवाई के दौरान उपस्थिति कम रही। जो ग्रामीण स्थल पर पहुंचे, उन्हें भी अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। इससे नाराज ग्रामीण विरोध दर्ज करा वापस लौट गए।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर और सचिव प्रशांत झा ने जनसुनवाई का विरोध जताते हुए कहा कि देश में सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल कोरबा जिला के लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और आम जनता कई प्रकार की प्रदूषणजनित बीमारियों के शिकार होंगे। विस्थापन प्रभावितों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए बिना फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करके जनसुनवाई की जा रही है। भू-विस्थापितों के पुराने लंबित रोजगार प्रकरणों, मुआवजा, बसावट आदि की समस्याओं का निराकरण नही किया जा रहा और न हीं बढ़ते प्रदूषण और गिरते जल स्तर पर ध्यान दिया जा रहा।

कोरबा जिले का विकास और प्रगति होगी पहली प्राथमिकता

- आकांक्षी जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों को केंद्रित करने के दिए निर्देश

कोरबा। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं आकांक्षी जिला कोरबा के प्रभारी रजत कुमार ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में आकांक्षी जिले के निर्धारित संकेतकों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं योजनाओं का लाभ जिले के लोगों तक पहुंचे इसके संबंध में संबंधित विभागों से चर्चा की और आकांक्षी जिले में लक्ष्य प्राप्ति तक सतत् कार्य करने के निर्देश दिए। संयुक्त सचिव श्री रजत कुमार ने कोरबा जिले में विकास की अपार संभावनाएं बताते हुए कहा कि वे पहले भी कोरबा जिले में कार्य कर चुके हैं। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो और आकांक्षी जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कोरबा जिला विकास तथा प्रगति की राह में आगे बढ़े यह उनकी प्राथमिकता में होगी। इस दौरान कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक उदय किरण भी उपस्थित थे।

बैठक में कुमार ने आकांक्षी जिले की अवधारणा के संबंध में कहा कि हम सभी की आकांक्षा यह होनी चाहिए कि हमारे जिले के लोगों का भी राज्य और देश के अन्य सामान्य जिलों के लोगों का जीवन स्तर समान हो। हमारे जिले में समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं हो। कोई भी बच्चा कुपोषित न हो, सभी गर्भवती

माताओं का पंजीयन हो और उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच हो, बच्चों का शतप्रतिशत टीकाकरण हो। हर गांव तक सड़क हो, लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। खेतों में सिंचाई की सुविधा हो, हर गांव में बिजली हो, हर पंचायत में इंटरनेट की भी सुविधा हो, बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो, यही हमारी आंकाक्षा होना चाहिए और जब तक हम यह सब लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक सतत् कार्य करते रहना होगा। जिले में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के संबंध में कहा कि संस्थागत प्रसव हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाए। सभी गर्भवती माताओं का पंजीयन कर उनकी नियमित जांच की जाए, उन्हें पोषण आहार मिले। जिले में शतप्रतिशत बच्चों की टीकाकरण हो, कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए। यदि कोई बच्चा कुपोषित है तो उस बच्चे को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कर उसका समुचित इलाज कराया जाए। इन महत्वपूर्ण संकेतकों पर स्वास्थ्य विभाग को समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करना होगा। संयुक्त सचिव कुमार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया की मातृत्व स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य में दी जाने वाली सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

अरुण साव 9 को नगरी में सभा को करेंगे सम्बोधित

नगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार 9 जून को बजरंग चौक नगरी में 11:00 बजे सिहावा विधानसभा के केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी सम्मेलन को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी बस्तर महाराजा कमलचंद्र भंजदेव के साथ प्रदेश व जिला के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की श्रृंखला में शनिवार 10 जून 11:00 संयुक्त मोर्चा की बैठक नगरी एवं बेलरगांव का संयुक्त बेलरगांव में रखा गया है। मगरलोड मंडल कुकरेल मंडल का संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन ग्राम बोरसी में 11 जून को रखा गया है। जिसमें प्रदेश और जिला के शीर्ष नेता संबोधित करेंगे।

मंत्रालय का अधिकारी बताकर देता था फर्जी नियुक्ति पत्र

भिलाई। सुपेला थाना पुलिस ने मंत्रालय का बड़ा अधिकारी बताकर लोगों की नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़ितों को विश्वास दिलाने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र देता था। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि आशीष नगर रिसाली निवासी भूपेश देशमुख ने नयन चटर्जी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि नयन चटर्जी ने उसे और उसके दोस्त जगदीप साहू को एनडीपीसी नगरनार बचेली में जूनियर इंजीनियर की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की थी। आरोपी नयन चटर्जी खुद को मंत्रालय का अधिकारी बताकर प्रार्थी से पैसा लेकर उन्हें लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए थे और फिर उनका पैसा वापस नहीं किया। वहीं आरोपी ने रायपुर निवासी जगदीप साहू को सरकारी विपणन समिति मर्यादित में नौकरी लगाने के नाम ठगी की और आरोपी ने न तो उसकी नौकरी लगवाई न ही पैसा वापस किया। आरोपी नयन चटर्जी को लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी।

हाईटेंशन तार टूटकर खेत में गिरी, 5 मवेशियों की मौत

कवर्धा। कबीरधाम जिले के दशरंगपुर चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम अगरीखार में आज सुबह हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने विद्युत सप्लाई बंद कराया और इसके बाद खेत से मवेशियों को हटाया गया। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि आज सुबह दशरंगपुर पुलिस चौकी को सूचना मिली कि ग्राम अगरीखार में करंट की चपेट में आने से मवेशियों की मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विद्युत विभाग से संपर्क कर विद्युत सप्लाई बंद कराई और मवेशियों को खेत से हटाया। बताया जाता है कि खेत के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन तार टूटकर खेत में गिर गई थी। सुबह मवेशियों को झुंड चरते-चरते तार की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। शुक्र है कि हादसे के समय वहां कोई नहीं था। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग सही तरीके से मेंटनेंस का काम नहीं कर रही है, जिसके चलते हाईटेंशन का तार टूटकर खेत में गिर गया।

सीतामणी क्षेत्र का महापौर ने किया भ्रमण, जानी समस्याएं

कोरबा। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्र. 10 सीतामणी क्षेत्र के हटरीपारा, केंवट मोहल्ला, संजयनगर, वैष्णव दरबार आदि बस्तियों का भ्रमण करते हुए स्वच्छता संबधित सफाई व्यवस्था एवं नालियों की साफ-सफाई का जायजा लिया। महापौर ने हटरीपारा के समीप स्वच्छता दीदियों से स्वच्छता के संबंध में जानकारी हासिल करते हुए जाना कि कचरों का उठाव नियमित रूप से हो रहा है या नहीं। प्रत्येक घरों से कचरों का उचित प्रबंधन निश्चित करने का उन्हें निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी घर में कचरा छूटना नहीं चाहिए एवं जो भी परिवार ट्रिपल आर. के तहत पुरानी घरेलु रद्दी पड़ी वस्तुएँ यदि देना चाहें तो उसे सेंटर में ले जाकर जमा करें ताकि जरूरतमंदो को ये वस्तुएँ उपलब्ध कराई जा सके। भ्रमण के दरम्यान महापौर ने लोगों की समस्याएँ सुनी तथा वार्डवासियों की छोटी-छोटी मांगे जैसे नालियों का कहीं टूट-फूट होना, नालियों में ढक्कन लगवाने की मांग तथा चबूतरा निर्माण की मांग रखे जाने पर महापौर के साथ चल रहे अधिकारियों को उनकी मांगों का त्वरित निदान करने हेतु आदेशित किया।

अपने अधिकार, सामाजिक उत्थान के लिए जागरूकता व संगठित होना जरुरी है: अंगेश

धमतरी। छग पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ जिला धमतरी के द्वारा ब्लाक नगरी के ग्राम उमरगांव में पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ का स्थापना दिवस 6 जून दिन मंगलवार को बाजार चौक रंगमंच मे मनाया गया।कार्यक्रम का शुभारम्भ भारत माता के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर किया गया।स्थापना दिवस के अवसर पर जिलाध्यक्ष अंगेश हिरवानी ने बताया की समाज की अधिकार के लिए संघर्ष करने व समाजिक उत्थान की उदेश्य से लोगो को जागरूक कर एक जुट करने के लिए वर्ष 2012 छै:जूनको बस्तर चारामा से संगठन तैयार किया गया।जो आज तक निरंतर अपनी अधिकार की लड़ाई जारी रखा है। अंगेश हिरवानी ने आगे कहा की अपने अधिकार की लड़ाई को आगे जारी रखने व संगठन की अच्छी मजबूत्ती के लिए लोगो को बिना किसी भेदभाव के आगे आना व जागरूक होना बहुत जरुरी है।क्योंकि आज की स्थिति मे हमारा आरक्षण राजनीति के भेट चढ़ गया।

11 वां वेतनमान पर समझौता, कोयला मंत्री ने जताई सहमति

कोरबा। कोयला कामगारों के 11 वां वेतन समझौता पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सहमति जता दी। 19 प्रतिशत मिनिमम गारंटी बेनीफिट एमजीबी समेत अन्य मुद्दों को लेकर मिले श्रमिक संघ प्रतिनिधियों को उन्होंने आश्वस्त किया कि कामगारों को नए वेतनमान का लाभ एक जुलाई से मिलने लगेगा।

दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जेबीसीसीआई सदस्य व श्रमिक संघ प्रतिनिधि मंडल ने कोयला मंत्री के समक्ष वेज बोर्ड के अलावा मेडिकल अनफिट, फीमेल वीआरएसए एक जनवरी 2017 से ग्रेच्युटी भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से रखा। उन्होंने 9.4.0 को समान रूप से लागू किए जाने की बात प्रमुखता से करही। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल से 9.4.0 के बारे में जानकारी ली। चेयरमैन अग्रवाल ने बताया कि इस मुद्दे पर एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

इन तीनों मुद्दों को लेकर कोयला मंत्री जोशी ने चेयरमैन अग्रवाल से जल्द बैठक बुलाने कहा। कोयला मंत्री जोशी ने कहा कि जेबीसीसीआइ 11 के ऊपर सरकार की मुहर लगना आवश्यक है, इसलिए दो-तीन दिन के अंदर फाइल आते ही, हम अनुमोदन कर देंगे। बैठक में एचएमएस से नाथूलाल पांडेय, इंटक से एसक्यू जमा, बीएमएस से सुधीर घुरडे, सीटू से डीडी रामनदंन व एटक से हरिद्वार सिंह सम्मिलित हुए।

एसईसीएल को कोयला मंत्री पुरस्कार से नवाजा गया

साउथ इस्टर्न कोलफि ल्डस लिमिटेड एसईसीएल को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी के सफल क्रियान्वयन के लिए कोयला मंत्री पुरस्कार 2022-23 में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी से एसईसीएल सीएमडी डा प्रेम सागर मिश्रा को दिया गया। प्रतिष्ठित कोयला मंत्री पुरस्कार के तृतीय संस्करण के समारोह में कोयला सचिव, भारत सरकार अमृत लाल मीणा और अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड प्रमोद अग्रवाल, एसईसीएल निदेशक तकनीकी संचालन एसके पाल व कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी का कार्यांवयन सीआइएल वन ईआरपी प्रोजेक्ट पेंशन के तहत एसईसीएल में लागू किया गया है। इसमें सात मुख्य व्यवसाय प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे उत्पादन योजना, वित्त और नियंत्रण, संयंत्र रखरखाव, बिक्री और वितरण, परियोजना प्रणाली, मानव पूंजी प्रबंधन और सामग्री प्रबंधन।

18 साल बाद खुले स्कूलों के 900 से ज्यादा बच्चों ने उठाया समर कैम्प का लाभ

बीजापुर। पुन: संचालित स्कूलों के 150 गांव से आये 1000 बच्चों का पेकोर पंडुम फेज 2 समर कैम्प बीते दिनों ज्ञान गुड़ी एजुकेशन सिटी में सम्पन्न हुआ । एक सप्ताह के समर कैम्प में दुर्गम और अतिसंवेदनशील इलाको के बच्चों ने कला, शिल्प, खेल, नृत्य और बुनियादी शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल की। समापन अवसर पर बच्चों ने सीखी हुई गतिविधियों का मंच पर प्रदर्शन कर खूब वाहवाही लूटी और अपने अनुभव बयान किये।

इस अवसर पर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए पेकोर पंडुम फेज 2 को बदलाव का माध्यम बताया। कलेक्टर ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें व्यक्तिगत रूप से खुशी हो रही है जिसमें इतने सारे बच्चों ने पहली बार बीजापुर तक सफर किया और इतने बड़े आयोजन के हिस्सा बने। इस आयोजन से निश्चित रूप से बच्चो के सोच और समझ का विकास होगा तथा उनकी छिपी प्रतिभाओं को निखारने का रास्ता बनेगा । यही बच्चे कल शांति और विकास के लिए अपने गांव में नई पहल शुरू कर सकेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम ने मंच से बच्चों की हौसलाअफजाई की और आयोजन के लिए जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की सराहना की। समापन कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीत- सुनो गौर से दुनिया वालो, लुंगी डांस, जय हो जैसे गीतों पर आकर्षक डांस कर खूब वाहवाही लूटी। बच्चों ने हिंदी और गोंडी में गीत गाने के साथ हाकिम का चिमटा नाटक की मंचीय प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी बलीराम बघेल ने अतिथियों का स्वागत किया और अंत मे सफल कार्यक्रम के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन और संयोजन एपीसी मोहम्मद ज़ाकिर खान द्वारा किया गया।

पेकोर पंडुम फेज 2 में शामिल सभी बच्चे 18 साल बाद खोले गए स्कूलों से शामिल किए गए। ये सभी इलाके माओवाद प्रभावित और अतिसंवेदनशील माने जाते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी को दिखाया आईना

नईदिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने चिर-परिचित अंदाज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलते हुए उन्हें भविष्य की ओर देखने में अक्षम बताया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह केवल पीछे (रियरव्यू मिरर) देखकर भारतीय कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 'एक के बाद एक हादसों' का कारण बन रही है। इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन लोगों का संज्ञान लेने के लिए 'रियरव्यू मिरर' में देखा जाना चाहिए, जो देश की संस्थाओं को कलंकित और बर्बाद करने निकले हैं। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि 2047 तक भारत दुनिया का अव्वल राष्ट्र बन जाएगा।

मप्र में 12 को चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगी प्रियंका

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर दौरे पर जाएंगी। इस दौरान वह पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। साथ ही साथ प्रियंका गांधी पार्टी की पांच गारंटी का भी ऐलान कर सकती हैं। फिलहाल मध्यप्रदेश में प्रियंका के दौरे को लेकर राजनीति गर्म होती दिखाई दे रही है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की ओर से पांच गारंटी देने की बात की जा रही है। कर्नाटक चुनाव में भी पांच गारंटी के दम पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कर्नाटक चुनाव में मिली इस जीत के बाद कांग्रेस आगामी चुनाव में भी 5 गारंटी को जारी करने के बात कह रही है। प्रियंका गांधी महाकौशल क्षेत्र से विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी। यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वर्चस्व माना जाता है।

भाजपा ने सिसोदिया को फर्जी मुकदमे करके जेल में डाला है

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक शैक्षणिक संस्थान के उद्घाटन के मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम को याद करते हुए भावुक हो गए। मुख्यमंत्री बाहरी दिल्ली के बवाना के दरियापुर गांव में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें झूठे मामले दर्ज कर जेल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मनीष ने अच्छे स्कूल नहीं बनाए होते, तो वे उन्हें जेल में नहीं डालते। वे शिक्षा क्रांति को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम शिक्षा क्रांति को खत्म नहीं होने देंगे। भाजपा पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये लोग चाहते है कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए लेकिन हम इसे होने नहीं देंगे। इस दौरान समर्थकों ने केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा क्रांति की शुरुआत की थी और उनका सपना था कि दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले।

गहलोत और पायलट के बीच सुलह का फार्मूला तैयार: रंधावा

जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है। इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस के हाईकमान की कोशिश है कि किसी भी तरह दोनों नेताओं के बीच सुलह हो जाए ताकि चुनावों में आपसी फूट का फायदा भाजपा को न हो। पायलट के नई पार्टी बनाने की खबरों का राजस्थान के प्रभारी कांग्रेस महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खंडन किया है। जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रंधावा ने ये भी कहा कि सुलह का फार्मूला तैयार है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट दोनों ही फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि सचिन पॉयलट के कांग्रेस से अलग होने को केवल मीडिया मुद्दा बना कर उठा रहा है।

फारुख अब्दुल्ला से मिले पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा

बेंगलुरु। नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और जनता दल (सेकुलर) के अध्यक्ष ने बुधवार को बेंगलुरु में मुलाकात की। नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला और जेडी (एस) प्रमुख एचडी देवगौड़ा के साथ जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी भी बातचीत में उपस्थित थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब विपक्ष एकजुटता के अलावा तीसरा फ्रंट भी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा सकता है। एक ओर जहां पूरे विपक्ष ने रेल हादसे पर भाजपा सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा और रेल मंत्री वैष्णव के इस्तीफे की मांग की तो वहीं पूर्व पीएम देवगौड़ा ने रेल मंत्री के कामों की सराहना की थी। उन्होंने यहां तक भी कहा कि रेल मंत्री ने इस्तीफे की मांग करना बेहद गलत है। अनुचित है। वहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता एचडी कुमार स्वामी ने भाजपा की थोड़ी आलोचना जरूर की थी लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने इनकार न करते हुए कहा था कि देखते हैं।

नोएडा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक

हम सभी चुनावों के लिए तैयार : जेपी नड्डा

लखनऊ। भाजपा 2024 चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मैदान में उतर चुके हैं। वह लगातार लोगों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नोएडा में टिफिन मीटिंग की। टिफिन मीटिंग में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए वे कैसे काम कर रहे हैं, इसकी भी समीक्षा की। हम 2024 के चुनाव सहित सभी चुनावों के लिए तैयार हैं।

टिफिन मीटिंग 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी के मेगा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा है। इस दौरान भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख भूपेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष पंकज सिंह, गौतम बौद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर सहित अन्य लोग नड्डा के साथ रहे। 'टिफिन बैठक' भाजपा की 2024 के आम चुनाव से पूर्व जनता तक पहुंच कायम करने के बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है। इससे पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं की एक बैठक हुई थी। यह बैठक 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली थी। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे।

सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भाजपा की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठित मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ अगले लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से अभी से ही तैयारी शुरू की जाए, इसको लेकर कि नेताओं के बीच चर्चा हुई है। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में कई

अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें कई प्रदेश अध्यक्षों को बदलने की तैयारी है। साथ ही साथ कई प्रदेश के प्रभारियों को भी बदला जा सकता है। कई नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। चुनाव के मद्देनजर भाजपा कई बड़े फैसले कर सकती है।

पांच राज्य में विधानसभा और 2024 में आम चुनाव

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस साल 5 राज्य में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाला है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। लगातार दो राज्य हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा को मात देकर झटका दिया है। बीजेपी नेतृत्व इसको लेकर गंभीर हो गया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस सत्ता में है। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हैं जहां भाजपा का शासन है। तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं, जहां 2014 में राज्य के गठन के बाद से भारत राष्ट्र समिति शासन कर रही है।

भाजपा की कोशिश जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की है वहीं मध्य प्रदेश में सत्ता बचाए रखने की भी उसके समक्ष चुनौती है। तेलंगाना में भी भाजपा बीआरएस को पटखनी देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 65 सीट हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले संगठनात्मक तंत्र की समीक्षा के साथ ही उसे और मजबूत बनाने के मकसद से पिछले 24 घंटे में मैराथन बैठकें कीं।

सूत्रों ने बताया कि भाजपा कुछ राज्यों में अपने संगठन में कुछ बदलाव कर सकती है और अपने पदाधिकारियों को नई भूमिकाएं सौंप सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से हारने के बाद, भाजपा आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

मोदी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 143 रुपये की बढ़ोतरी की

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले में धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने 2023-24 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 143 रुपये बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। इस कदम का मकसद किसानों को धान की खेती के लिए प्रोत्साहन देना और उनकी आमदनी बढ़ाना है। एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में 2023-24 के फसल वर्ष के लिए खरीफ (गर्मियों) की सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी गई। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने सीसीईए की बैठक के बाद मीडिया से कहा कि कृषि क्षेत्र में हम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर समयबद्ध तरीके से एमएसपी तय करते हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस साल एमएसपी में अधिक बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसे समय जबकि खुदरा मुद्रास्फीति नीचे आ रही है, एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सामान्य ग्रेड के धान का एमएसपी 143 रुपये बढ़ाकर 2,040 रुपये से 2,183 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। 'ए' ग्रेड के धान का एमएसपी 163 रुपये बढ़ाकर 2,203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक 10.14 प्रतिशत की वृद्धि मूंग में की गई है। मूंग का एमएसपी अब 8,558 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। पिछले साल यह 7,755 रुपये प्रति क्विंटल था।

शरद पवार का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले-

देश में भाजपा विरोधी लहर, देश की जनता चाहती है बदलाव

औरंगाबाद। कर्नाटक चुनाव में भाजपा को मिली शिकस्त के बाद विपक्ष की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर हैं। इसको लेकर महागठबंधन से लेकर तरह-तरह की रणनीति अपनाई जा रही हैं। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में देश में भाजपा विरोधी लहर है और जनता कर्नाटक विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखते हुए बदलाव चाहती है।

शरद पवार ने मीडिया से कहा कि अगर लोगों की यही मानसिकता रही तो देश आगामी चुनावों में बदलाव देखेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में छोटी-छोटी घटनाओं को धार्मिक रंग दिया जा रहा है, जो अच्छा संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, यहां कांग्रेस पांच साल के अंतराल के बाद सत्ता में वापस आई।

देश में लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी अगले साल के अंत में होने वाले हैं। शरद पवार ने कहा कि परिदृश्य को देखते हुए, मुझे लगता है कि भाजपा विरोधी लहर चल रही है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों को देखते हुए, लोग बदलाव के मूड में हैं। अगर लोगों की यह मानसिकता बनी रही, तो देश में बदलाव आएगा। यह बताने के लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है।

जब शरद पवार से हाल के दिनों में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति और हिंसा की कुछ घटनाओं के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था करने के लिए सरकार जिम्मेदार हैं। अगर सत्ताधारी दल और उनके लोग सड़कों पर उतरते हैं और दो धर्मों के बीच दरार पैदा करते हैं, तो यह अच्छा संकेत नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि अगर औरंगाबाद में किसी

व्यक्ति का पोस्टर दिखाया जाता है, तो पुणे में हिंसा की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा होने दिया जा रहा है। शरद पवार ने आरोप लगाया कि हाल ही में हमने अहमदनगर के बारे में सुना। आज, मैंने कोल्हापुर से एक खबर देखी। लोग सड़कों पर निकल आए, और फोन पर संदेश भेजने की एक छोटी सी घटना को धार्मिक रंग देना अच्छा संकेत नहीं है। सत्ताधारी दल ऐसी चीजों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। राकांपा प्रमुख पवार ने राज्य में कृषि संबंधी मुद्दों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कपास उत्पादक किसानों की स्थिति गंभीर है। कपास की खरीद करनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर किसान सड़क पर उतरने का फैसला करते हैं तो एनसीपी उनके पीछे होगी। शरद पवार ने कहा कि सरकार का नजरिया उतना सकारात्मक नहीं है जितना होना चाहिए। कोटा निर्यात के लिए तय नहीं है और दूसरी तरफ चीनी के दाम गिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादकों के लिए फायदेमंद नहीं है।

बृजभूषण के खिलाफ जांच शुरू होना राहत की बात: शरद पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच शुरू होना राहत की बात है। बृजभूषण पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पवार ने पत्रकारों से कहा कि प्रदर्शन कर रहे पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि पहले जांच की जाएगी, फिर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, ''जांच शुरू होना राहत की बात है।'' पहलवान भाजपा के नेता एवं सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

वेस्टइंडीज ने यूएई को 78 रन से हराकर श्रृंखला में विजयी बढ़त बनाई

शारजाह। सलामी बल्लेबाजों ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स के अर्धशतक और दोनों के बीच पहले विकेट की शतकीय साझेदारी से वेस्टइंडीज ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को यहां यूएई को 78 रन से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। वेस्टइंडीज ने कप्तान के रूप में शाई होप और कोच के रूप में डेरेन सैमी ने यह पहली श्रृंखला जीती है। वेस्टइंडीज की टीम किंग के 64 और चार्ल्स के 63 रन और दोनों के बीच पहले विकेट की 129 रन की साझेदारी के बावजूद 49.5 ओवर में 306 रन पर आउट हो गई। वेस्टइंडीज के लिए केसी कार्टी (32), होप (23) और केवेम हॉज (26) अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे।

ओडियन स्मिथ ने अंत में 24 गेंद में 37 रन की आक्रामक पारी खेलकर टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। यूएई की तरफ से जहूर खान सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 44 रन देकर तीन विकेट चटकाए। अली नसीर, संचित शर्मा और अयान अफजल खान ने भी दो-दो विकेट हासिल किए। किंग ने 70 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और चार छक्के मारे जबकि चार्ल्स ने 47 गेंद का सामना करते हुए आठ चौके और तीन छक्के जड़े। यूएई ने इसके जवाब में 95 रन पर ही पांच विकेट गंवा दिए थे लेकिन अली नसीर (57) और बासिल हमीद (49) के बीच छठे विकेट की 80 रन की साझेदारी से हार के अंतर को कम करने में सफल रही। मेजबान टीम ने सात विकेट पर 228 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से हॉज ने 46 जबकि रोस्टन चेस ने 49 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। वेस्टइंडीज ने पहला एकदिवसीय मुकाबला 88 गेंद शेष रहते सात विकेट से जीता था।

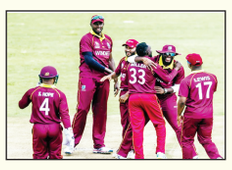

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 350 अंक उछला निफ्टी 18,700 के पार

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रत संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में सेंसेक्स 350 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी ने भी 127 अंको की बढ़त दर्ज की। कारोबार के अंत में निफ्टी 18,726.40 पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 350.08 अंक यानी 0.56 फीसदी की बढ़त के साथ 63,142.96 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 63,196.43 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 62,841.95 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 127.40 अंक यानी 0.68 फीसदी चढ़ा। निफ्टी दिन के अंत में 18,726.40 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,738.95 की उंचाई तक गया और नीचे में 18,636.00 तक आया।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के लिए 'अभी नहीं, तो कभी नहीं' का समय : सेमी सीईओ

नईदिल्ली। भारत के पास वह सब कुछ है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग में सफल होने के लिए जरूरी है, लेकिन उसे अब भी अपनी विश्वसनीयता कायम करने की जरूरत है। सेमी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मनोचा ने कहा कि डेढ़ साल पहले भारत इस क्षेत्र में 'शून्य' था। वहीं 2024 तक भारत में 100 सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप होंगे। उन्होंने कहा कि चिप बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना, बड़े प्रतिभा पूल और कौशल कार्यक्रम की वजह से आज सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ''भारत के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में यह 'अभी नहीं तो कभी नहीं' का समय है। यह रफ्तार पकड़ने से काफी वर्ष लग जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक फिर रीपो रेट रख सकता है स्थिर

नईदिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगातार दूसरे महीने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने की संभावना है। एक सर्वे में 40 अर्थशास्त्रियों ने अनुमान जताया है कि आरबीआई गुरुवार को रीपो रेट को 6.50 फीसदी पर अपरिवर्तित रखेगा। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले महीनों में महंगाई और कम हो सकती है। उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 18 महीने के निचले स्तर 4.7 फीसदी पर आ गई। आरबीआई ने महंगाई को 2 से 6 फीसदी के बीच रखने का लक्ष्य रखा है। भारत के लेटेस्ट तिमाही वृद्धि के आंकड़े पिछले वित्त वर्ष के अनुमान से अधिक रहे। यह अब बढ़कर 7.2 फीसदी पर पहुंच गया है। भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्थशास्त्री राहुल बाजोरिया ने कहा, स्थिर विकास और कम होती महंगाई के बीच, आरबीआई वैश्विक घटनाओं को किनारे से देखने का विकल्प चुन सकता है, विशेष रूप से भारत की बेहतर मैक्रो स्टेबिलिटी को देखते हुए।

मारुति ने लॉन्च की जिम्नी थार से सीधी टक्कर

नईदिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को स्पोर्ट्स यूटिलिटी वेहिकल सेगमेंट मे अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों के तहत 'जिम्नी' उतारी है। इसकी दिल्ली शोरूम में कीमत 12.74 लाख रुपये से 15.05 लाख रुपये के बीच है। कंपनी की निगाह एसयूवी सेगमेंट में शीर्ष स्थान हासिल करने पर है। जिम्नी के मैनुअल ट्रिम्स की कीमत 12.74 लाख रुपये से 13.85 लाख रुपये के बीच है, जबकि 4-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रिम्स की कीमत 13.94 लाख से 15.05 लाख रुपये के बीच है। पांच दरवाजों वाला मॉडल, जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल मोटर है, दो ट्रिम्स- जेटा और अल्फा में आएगा और इसे नेक्सा डीलरशिप के जरिये बेचा जाएगा।

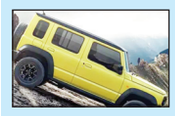

विपरीत परिस्थितियों में उम्मीद जगाते हैं जीडीपी के आंकड़े

अजय बग्गा

वित्त वर्ष 2023 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। विकास की तमाम उम्मीदों को छोड़ते हुए जनवरी से मार्च, 2023 की तिमाही में भारतीय जीडीपी 6.1 फीसदी की दर से बढ़ी। इसने संपूर्ण वित्त वर्ष 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की समग्र वृद्धि को 7.2 फीसदी के स्तर पर पहुंचा दिया। अन्य शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत के बाद इंडोनेशिया का स्थान है, जिसने पिछले वर्ष 5.3 फीसदी की दर से विकास किया। सरकारी व निजी पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी, कृषि एवं सेवा क्षेत्र में बेहतर विकास के कारण भारत की जीडीपी उम्मीद से ज्यादा रही, जबकि निजी खपत की दर सुस्त रही।

विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन को देखें, तो विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि मार्च तिमाही में बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई, जबकि एक साल पहले यह 0.6 प्रतिशत थी। खनन क्षेत्र में चौथी तिमाही में जीवीए वृद्धि पिछले वर्ष के 2.3 प्रतिशत की तुलना में 4.3 प्रतिशत थी। निर्माण क्षेत्र मार्च तिमाही में 10.4 प्रतिशत बढ़ा, जो 2021-22 की इसी अवधि में 4.9 प्रतिशत था। कृषि क्षेत्र की वृद्धि पिछले वर्ष के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई। व्यापार संतुलन में भी सुधार हुआ है, क्योंकि निर्यात की तुलना में आयात में अधिक गिरावट आई। इसने जीडीपी के आंकड़े को बढ़ावा दिया। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में गिरावट ने भी विकास दर को ऊपर उठाने में मदद की।

जीडीपी के आंकड़े विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत के लिए उम्मीद बढ़ाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अर्थव्यवस्था के सामने जोखिम नहीं है।

विशेष रूप से मानसून के रुख और वैश्विक मंदी के जोखिमों को लेकर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन इस शानदार प्रदर्शन ने वित्त वर्ष 2024 में आर्थिक गतिविधियों के विकास की गति को छह फीसदी से अधिक होने की उम्मीद बढ़ा दी है।

भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार का मानना है कि चालू वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था में ठोस प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण मांग में सुधार के संकेत हैं, और शहरी मांग कायम है और यात्री वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। बढ़ती ग्रामीण मजदूरी, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, और कम खाद्य मुद्रास्फीति की उम्मीद ग्रामीण मांग दृष्टिकोण के लिए अच्छा संकेत है। हालांकि, मानसून के मौसम में अल नीनो की स्थिति कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय के लिए एक प्रमुख जोखिम है। मानसून में देरी हुई है, पर अब भी मौसम विभाग सामान्य मानसून की भविष्यवाणी कर रहा है। मानसून संबंधी किसी भी जोखिम या भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को छोड़कर, भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के प्रारंभिक अनुमान को पार कर सकती है। अल नीनो द्वारा मॉनसून की बारिश को प्रभावित करने पर इसमें 0.5 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।

उम्मीद है कि जीडीपी के शानदार आंकड़े को देखते हुए रिजर्व बैंक इस साल की दूसरी छमाही में संभावित वैश्विक मंदी के जोखिमों के बावजूद अपने नीतिगत रुख पर कायम रहेगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रमुख संकेतकों पर पकड़ बरकरार है, जिसमें जीएसटी संग्रहण, पीएमआई (विनिर्माण से ज्यादा सेवा क्षेत्र में वृद्धि), उद्योग ऋण में वृद्धि, स्टील एवं सीमेंट का उत्पादन और व्यापार घाटे में कमी, आदि शामिल हैं।

रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों, वित्तीय स्थितियों और पिछले सुधारों से अपेक्षित लाभांश में मदद करता है। वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता वस्तुओं और खाद्य कीमतों में नरमी, अच्छी कृषि, संपर्क-गहन सेवाओं में निरंतर उछाल और पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान विकास की गति बनाए रखने में मदद कर रहा है, भले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो।

फिर राहुल को सीरियसली क्यों ले रही भाजपा

चंद्रभूषण

राहुल गांधी के अमेरिका और ब्रिटेन में दिए हुए कुछ बयानों से सत्तारूढ़ खेमे में नाराजगी है। एक तो यह कि राहुल गांधी विदेश में जो बयान जारी कर रहे हैं, वे किसी खास राजनीतिक दल के विरोध तक सीमित नहीं हैं। संपूर्णता में देखें तो वह राष्ट्र का विरोध है, और इससे राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह कही जा रही है कि इन बयानों से देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसका सारा दोष कांग्रेस पर जाएगा। ये आधार थोड़े अजीब लगते हैं और इसकी वजह भी है। राहुल की राजनीति का खत्म होना तो बीजेपी के लिए विशेष चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, न उसके समर्थकों के लिए। उनकी राजनीति खत्म करने के लिए इस पक्ष की ओर से अब तक काफी प्रयास किए गए हैं। राहुल गांधी के लिए 'पप्पू' नाम से बाकायदा अभियान चलाया गया। कई बार आधिकारिक तौर पर भी कहा गया है कि राहुल गांधी को भारत में कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के अनुसार जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, उसकी बात को खुद बीजेपी क्यों इतनी गंभीरता से ले रही है? खासकर तब, जबकि वह किसी जिम्मेदार पद पर भी नहीं हैं। राहुल गांधी न तो सांसद हैं, न ही कांग्रेस के किसी जिम्मेदार पद पर हैं। राहुल गांधी बाहर जाकर कह रहे हैं कि कुछेक कारणों से उन्हें संसद से बाहर कर दिया गया। इस एक बात को छोड़ दें तो बाकी जो सारे मामले हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे बनाए हुए मामले हैं या मिसरिप्रेजेंटेशन के मामले हैं। जो दिक्कतें और समस्याएं हैं, उन पर पहले से ही दुनिया में चर्चा होती रही है। ऐसे ही भारत के वित्तीय तौर तरीकों में कुछ समस्या है, तो यह मसला सबसे पहले राहुल गांधी ने नहीं, बल्कि जॉर्ज सोरोस ने उठाया था। जॉर्ज सोरोस दुनिया के वित्तीय दायरे में एक बहुत बड़ा नाम है। जिन बातों पर सत्ता पक्ष को इतना क्षोभ है, वे सारी बातें राहुल गांधी ने किसी भाषण में या किसी एकतरफा बयान में लिखकर जारी नहीं की हैं। ये चीजें सवाल-जवाब के दौरान सामने आई हैं। सवाल-जवाब को आप भारत में नियंत्रित कर सकते हैं शायद, लेकिन विदेश में कोई राजनेता पब्लिक डोमेन में कुछ कहता है तो उस पर सवाल करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। और कोई सवाल कर रहा है तो उसका जवाब भी मिलेगा। ऐसे में यह आपत्ति उचित नहीं लगती कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। यह कांग्रेस पार्टी की ओवरसीज शाखा की तरफ से किया गया आयोजन था। यह ब्रिटेन में भी हुआ था, अमेरिका में भी हुआ। इसमें ज्यादातर कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थक लोग ही आते हैं, लेकिन विरोधियों को भी आने से रोका नहीं जाता। इसीलिए अमेरिका में एक ऐसे ही आयोजन में कुछ खालिस्तानी तत्वों ने राहुल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें कोई नहीं रोक सका। जिन बातों पर सबसे ज्यादा ऐतराज है, उनमें सबसे ऊपर है भारत में अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों को उत्पीड़ित बताया जाना। लेकिन ये खबरें राहुल गांधी के बयान देने से बहुत पहले से दुनिया भर के अखबारों में छप रही हैं। ऐसी खबरें भारत में भी खूब छपती हैं। इनको आधार बनाकर बाकायदा चुनाव जीते जाते हैं। इसके आगे जाएं तो कुछ ही समय पहले अमेरिका में बीजेपी समर्थक एक जगह पर बुलडोजर का रोड शो निकाल रहे थे। वहां कुछ लोगों ने ऐतराज किया तो वहां की स्थानीय सरकार ने अपनी तरफ से पहलकदमी लेकर उसे बंद कराया।

मोदी सरकार के नौ साल का प्रचार संकेत है

विनोद अग्निहोत्री

क्या लोकसभा चुनाव अपने तय वक्त से पहले हो सकते हैं? क्या उन्हें इसी साल नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ कराया जा सकता है? क्या मोदी सरकार की नौ साल की उपलब्धियों के प्रचार पर जोर इसका संकेत है? यह चर्चाएं और सवाल इन दिनों सियासी गलियारों की कानाफूसी में तैरने लगे हैं। हालांकि अभी यह बातें सत्ता और सियासत के गलियारों में आम नहीं हुई हैं, लेकिन सत्ता के उच्च स्तर पर कुछ खास लोगों ने इस तरह के संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि सरकार और भाजपा के शीर्षस्थ स्तर पर इसे लेकर न सिर्फ मंथन चल रहा है, बल्कि यह आकलन भी हो रहा है कि लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों को साथ कराने में कितना सियासी फायदा या नुकसान है।

वैसे तो भाजपा नेता अकसर कहते हैं कि उनका दल किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार रहता है, लेकिन इन दिनों जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह शीर्ष स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है, मंत्रियों और सांसदों को जिले-जिले भेजकर मोदी सरकार के नौ साल की उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है और प्रचार का सारा जोर मोदी सरकार के नौ साल के नारे पर है, उससे संकेत हैं कि भाजपा किसी भी समय (समय से पूर्व या समय पर) लोकसभा चुनावों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही है, जबकि विपक्ष अभी एकजुटता की रट से आगे नहीं बढ़ सका है। मई के आखिरी सप्ताह में मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा ने मीडिया के साथ जो संवाद किया, उसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार के नौ साल के कामकाज पर सारा जोर दिया और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जो प्रस्तुतिकरण (पीपीटी) दिखाया उसमें विस्तार से मोदी सरकार के नौ सालों की उपलब्धियों की तुलना यूपीए सरकार के दस साल के कामकाज से करते हुए बताया गया कि कैसे मोदी सरकार ने नौ सालों में कितना बेहतर काम किया है। भाजपा ने अपने प्रचार के लिए जो नया नारा गढ़ा है वह है %सेवा सुशासन और गरीब कल्याण।%

अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के भाजपा के एक दिग्गज नेता के मुताबिक जबकि अभी चुनावों में करीब एक साल है और आम तौर पर चुनाव से दो-तीन महीने पहले पार्टी अपने पूरे कार्यकाल की उपलब्धियों का ब्यौरा देती है। लेकिन इस बार जिस तरह दस साल पूरे होने से पहले ही नौ सालों के कामकाज और उपलब्धियों को इस तरह पेश किया जा रहा है मानों इसी साल लोकसभा के चुनाव होने

हैं, इससे साफ है कि सरकार और पार्टी के शीर्ष स्तर पर लोकसभा चुनावों को लेकर गंभीर मंथन हो रहा है।

इस मुद्दे पर सरकार और पार्टी के कुछ उच्च स्तरीय सूत्रों का कहना है जिस तरह 2022 के आखिर में हुए गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम के चुनावों में दो जगह हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम में भाजपा की हार हुई उससे पार्टी शिखर स्तर पर असहज हुई, लेकिन 2023 की शुरुआत में पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में भी भले ही कांग्रेस की करारी हार हुई, लेकिन भाजपा को जैसी उम्मीद थी वैसे नतीजे नहीं आए। त्रिपुरा में उसकी सरकार जरूर बनी लेकिन सीटें कम हुईं और स्थिरता के लिए उसे गठबंधन करना पड़ा। मेघालय में कोर्नाड संगमा की जिस पार्टी से गठबंधन तोड़कर भाजपा राज्य की सभी सीटों पर अकेली चुनाव लड़ी, वहां उसकी सीटें और मत प्रतिशत दोनों कम हुए। सिर्फ नगालैंड में जरूर भाजपा अपनी सहयोगी एनडीपीपी के सहारे कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकी। हालांकि पूर्वोत्तर के नतीजों को भाजपा ने अपनी प्रचार और मीडिया रणनीति से एक बड़ी विजय के रूप में प्रचारित करके अपने पक्ष में जो माहौल बनाया था, मई में हुए कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस के हाथों मिली करारी हार ने उसे बिगाड़ दिया। इसके बाद सरकार और पार्टी के उच्च स्तर पर देश के सियासी मूड और माहौल का आकलन शुरू हो गया। उधर भारत जोड़ो पदयात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में लगातार सुधार और विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस के मजबूत होने और सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ती विपक्षी दलों की गोलबंदी ने भाजपा में शीर्ष स्तर पर माथे पर बल ला दिए हैं। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में उन्हें जिस तरह भारतीय समुदाय और स्थानीय मीडिया ने गंभीरता से लिया और सुना है उससे भी भाजपा असहज है। दक्षिण से उत्तर की भारत जोड़ो पद यात्रा की कामयाबी के बाद से ही सितंबर में पश्चिम से पूरब तक की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की चलने वाली चर्चा भी कर्नाटक के नतीजों के बाद भाजपा के रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर रही है।

इन सूत्रों के मुताबिक मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले साल मार्च के बाद जरूरत से ज्यादा गरमी पड़ने की संभावना है और अगर ऐसा हुआ, तो लोकसभा चुनावों में मतदान कम होने की आशंका को भी भाजपा अपने मुफीद नहीं मानती है। हालांकि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ अच्छी खबरें सरकार को सुकून भी दे रही हैं। दो हजार रुपये की नोटबंदी ने आर्थिक मोर्चे पर कोई संकट नहीं पैदा किया और मोजूदा तिमाही की विकास दर भी अनुमान से ज्यादा रही है। खुदरा महंगाई में भी मामूली सी कमी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलने वाले फीड बैक ने पार्टी को सांसत में डाल दिया है।

राजस्थान में अगर कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का झगड़ा सिरदर्द है, तो भाजपा में भी वसुंधरा राजे को साधना भी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में हुई राजस्थान यात्रा में वसुंधरा को भी मंच पर ससम्मान बिठाया गया, लेकिन ग्वालियर राजपरिवार की बेटी महज इससे संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें राजस्थान भाजपा की पूरी कमान चाहिए और वह भी चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा के साथ। उधर गहलोत सरकार की अनेक लोकलुभावन योजनाओं और घोषणाओं ने सचिन की बगावत के बावजूद कांग्रेस को मुकाबले में ला दिया है। यह भी भाजपा की चिंता का सबब है। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना ने रेलवे में सुधार के सरकारी दावों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उधर कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी की कांग्रेसी घोषणा को बजरंग बली के सम्मान से जोड़ने की पूरी कवायद और प्रधानमंत्री मोदी के तूफानी प्रचार के बावजूद भाजपा की करारी शिकस्त ने हिंदुत्व के ध्रुवीकरण और मोदी मैजिक के हर समय संकट मोचक होने पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

बिहार, प. बंगाल और महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन को न दोहरा पाने की आशंका से परेशान भाजपा की दक्षिण भारत को लेकर जो उम्मीद थी कर्नाटक के नतीजों ने उस पर भी ग्रहण लगा दिया है। जिस तरह दिल्ली में यौन शोषण के मुद्दे पर महिला पहलवानों के आंदोलन को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों और किसान संगठनों का समर्थन मिलने से सरकार की छवि पर भी असर पड़ रहा है, जो आगे चलकर किसान आंदोलन जैसी शक्ल भी ले सकता है। सरकार को इस तरह की जानकारी भी मिल रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस, अग्निवीर, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों और जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष जिस तरह सरकार पर अपना दबाव बढ़ा रहा है और अगर यह इसी तरह चलता रहा तो अगले साल मार्च-अप्रैल तक सरकार के खिलाफ जनता का रुझान (एंटी इन्कंबेंसी) खासा बढ़ सकता है, जिसके नुकसान की भरपाई मुश्किल हो सकती है। बताया जाता है कि इन्हीं सब कारणों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ कराने का विचार हो रहा है। इसके पक्ष में तर्क हैं कि विपक्ष अपनी तैयारी अगले साल मार्च-अप्रैल के हिसाब से कर रहा है और अचानक चुनावों की घोषणा उसे संभलने का मौका नहीं देगी। राहुल गांधी अगर पश्चिम से पूरब की यात्रा पर निकलते हैं तो जल्दी चुनाव होने पर उन्हें अपनी यात्रा रोकनी पड़ेगी। साथ ही अगर विधानसभा चुनावों में भाजपा को अनुकूल नतीजे नहीं मिले तो पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल कमजोर हो जाएगा, जिसका असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों चुनाव साथ हो जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी की निजी लोकप्रियता का लाभ राज्यों के चुनावों में भी मिलेगा और भाजपा के लिए विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों दोनों जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि मोदी की छवि राज्यों में भाजपा के खिलाफ बने विरोधी माहौल और कमजोर स्थिति पर भारी पड़ जाएगी और जब मतदाता वोट डालने जाएंगे, तब वो मोदी के चेहरे पर ही वोट डालेंगे और दोनों ही जगह इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव जल्दी कराने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क यह भी है कि इसी साल सितंबर में नई दिल्ली में जी-20 देशों का शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिन पिंग समेत सभी वैश्विक नेता आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इनकी मेजबानी करेंगे बल्कि उनकी अपनी वैश्विक छवि भी बढ़कर विराट हो जाएगी। सरकार और भाजपा प्रधानमंत्री मोदी और भारत को विश्व गुरु के रूप में जनता के बीच प्रस्तुत करेगी और जी-20 की कामयाबी के प्रचार से आच्छादित माहौल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराकर इसका पूरा लाभ इसी तरह लिया जा सकेगा, जैसा 2009 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के बाद मनमोहन सिंह की सिंह इज़ किंग की छवि का लाभ कांग्रेस को मिला था।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

गरुडोपनिषद् (भाग-3)

गतांक से आगे...

पक्षिराज गरुड़, विष्णुवल्लभ (विष्णुप्रिय) तीनों लोकों के द्वारा पूजित किये जाने वाले, उग्र-भयंकर कालाग्नि के सदृश, कठोर नखों से युक्त, कठोर चञ्चु (चोंच) से युक्त, कठोर दाँत वाले, कठोर दाढ़ों वाले, कठोर पूँछ वाले, कठोर पंखों से लक्षित शरीर वाले भगवान् श्रीमहागरुड़ को नमस्कार है। आप आएँ, हे महागरुड़! अपने अनुशासित इस आसन पर आएँ, प्रवेश करें। दुष्टों के विष को दूर करें, दूर करें। जो विष स्पर्श मात्र से आ जाता है, उसे नष्ट करें, नष्ट करें। रेंगने वाले विषैले सर्पों के विष को दूर करें, दूर करें। प्रलीन (छिपे हुए) विष को दूर हटाएँ, दूर हटाएँ। सभी तरह के विषों को विनष्ट करें, विनष्ट करें। मारे-मारें, जलाएँ- जलाएँ, पचाएँ पचाएँ समस्त विषों को भस्मीभूत करें, भस्मीभूत करें। हुं फट् (योग मन्त्र के सहित गरुदेव की प्रसन्नता के लिए इस मन्त्र से आहुति समर्पित करें अथवा) आहुति समर्पित है।

आप चन्द्रमण्डल के सदृश हैं। आपकी मुष्टिका में सूर्यमण्डल स्थित है, ऐसे आप पृथ्वी मण्डल के सदृश मुद्राङ्गों वाले हे श्रीमहागरुड़! (आप) समस्त विषों का हरण करें-हरण करें, नष्ट करें। हुं फट् (बीज मन्त्र के सहित श्रीगरुड़ की प्रसन्नता के लिए) आहुति समर्पित है। (हे महागरुड़! आप विषधरों अथवा विषों को) क्षिप अर्थात् दूर फेंक दें। (इस निमित्त) आहुति समर्पित है। तत्कारि-मत्कारि (उनकी या हमारी) हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित हो रहा है, उसे (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों के विष (अर्थात् विषनाशक) विषरूपिणी, विष को दूषित, शोषित, नष्ट एवं हरण करने वाली, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसके द्वारा घातक विष को, अन्तलीन विष को प्रणाशक (नष्ट करने वाले) विष को नष्ट कर दिया गया।

विष को नष्ट करने में इन्द्र के वज्र ने सहयोग प्रदान किया। (इस निमित्त) आहुति समर्पित है। (उन) भगवान् महागरुड़ को नमस्कार है। भगवान् विष्णु के वाहन तीनों लोकों में पूजित, वज्रवत् कठोर नाखून एवं कठोर चोंच वाले तथा अपने शरीर को कठोर पंखों से अलंकृत करने वाले हे गरुड़देव! आप आएँ- आप पधारें। हे महागरुड़! आप आविष्ट (प्रविष्ट) हो करके विष को छिन्न-भिन्न कर दें। हुं फट् (बीज मन्त्र के सहित गरुड़देव के प्रसन्नतार्थ) आहुति समर्पित है।

क्रमशः ...

विश्व महासागर दिवसः जीने के लिए महासागरों को बचाना होगा

प्रियंका सौरभ

जीवन में महासागरों के महत्व को समझते हुए पर हम पृथ्वी वासियों का ध्यान महासागरों के अस्तित्व को अक्षुण्ण रखने की ओर अवश्य ही जाना चाहिए। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों का असर समुद्रों पर भी दिखने लगा है। समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर लगातार घटता जा रहा है और तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल में भारी मात्रा में प्रदूषणकारी तत्वों के मिलने से जीवन संकट में हैं। तेलवाहक जहाजों से तेल के रिसाव के कारण समुद्री जल के मटमैला होने पर उसमें सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुँच पाता, जिससे वहाँ जीवन को पनपने में परेशानी होती है और उन स्थानों पर जैव-विविधता भी प्रभावित हो रही है। महासागरों के तटीय क्षेत्रों में भी दिनों-दिन प्रदूषण का बढ़ता स्तर चिंताजनक है।

दुनियाभर में 8 जून के दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। महासागर पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी अहम भूमिका निभाते है। इसका मुख्य मकसद लोगों को समुद्र में बढ़ रहे प्रदूषण और उससे होने वाले

खतरों के बारे में जागरूक करना है। पृथ्वी पर महासागरों के बगैर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल ही लगता है, क्योंकि समंदर को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद उपयोगी माना जाता है, बावजूद इसके महासागरों में तेजी से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। महासागरों में गिरने वाले प्लास्टिक प्रदूषण के वजह से महासागर धीरे-धीरे अपशिष्ट होते जा रहे हैं। जिसका समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि समुद्री जीव गलती से प्लास्टिक को अपना भोजन समझ लेते हैं जिससे उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन महासागर के पारिस्थितिकी तंत्रों पर भारी पड़ रहा है और समुद्र में अधिकांश लोगों के जीवन के लिए एक विनाशकारी भविष्य का चित्रण करता है, इसलिए आज हमें समुद्र के वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभावों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए काफी आगे की जांच की आवश्यकता है। मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को घटाकर नीतिगत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा; शिपिंग और परिवहन; तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और बहाली; मत्स्य पालन, जलीय कृषि और स्थानांतरण आहार; और सीबेड में कार्बन भंडारण पर ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान भविष्यवाणियों के अनुसार, वार्मिंग परिदृश्य के आधार पर, क्षेत्रीय तापमान 2100 तक 3.5 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ने की संभावना है, जिससे ग्लेशियर की मात्रा में 36 से 64 प्रतिशत तक का महत्वपूर्ण नुकसान होगा। यह पानी के प्रवाह और इसकी उपलब्धता को प्रभावित करेगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल संसाधनों में घरेलू उपयोग, कृषि और जलविद्युत के लिए सीधे-सीधे प्रभावित होगा, सभी देशों को समुद्र के भीतर अक्षय ऊर्जा संसाधनों और ऊर्जा कुशल तटीय और अपतटीय बुनियादी ढांचे के अध्ययन और विकास के लिए समय रहते नए प्रयास शुरू करने चाहिए। और जीने के लिए महासागरों को बचाने में जुट जाना चाहिए।

भारत के करीब आए प्रचंड तो नेपाल में मच गया बवाल

रंजीत कुमार

हाल ही में अपने भारत दौरे में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और कई लंबित द्विपक्षीय समझौते और परियोजनाओं पर हस्ताक्षर भी किये। कृषि, ऊर्जा, संस्कृति, आवागमन, आपसी व्यापार और सुरक्षा से जुड़े ये समझौते निश्चित रूप से दोनों देशों के व्यापक हित में हैं। इसमें खास तौर से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात, धार्मिक समझौते के तहत रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं का पूरा किया जाना अहम है। ट्रांजिट समझौतों, रेल संपर्क बढ़ाने और विद्युत व्यापार जैसे अहम समझौतों के अलावा तेल पाइपलाइन का विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय संपर्क को आसान बनाने की प्रक्रिया शामिल है, जोकि निस्संदेह दोनों देशों के हित में है। इसके बावजूद नेपाल के लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा प्रचंड की भारत यात्रा की जोरदार आलोचना की जा रही है। विपक्षी दल प्रचंड के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। वे प्रचंड पर नेपाल को भारत के हाथों पूरी तरह से बेचने का आरोप लगा रहे हैं। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी-एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (यूएमएल), राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी), राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (एनआईपी) और नेपाल मजदूर किसान पार्टी (एनएमकेपी) सहित विपक्ष ने नेपाली संसद (प्रतिनिधि सभा) तक को चलने नहीं दिया। यह विरोध तब है जब प्रचंड के दौरे से पूर्व ही नेपाल के विदेश विभाग ने यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया था। उसने अपने बयान में कहा था, यात्रा दोनों देशों के सदियों पुराने बहुमुखी और सौहार्दपूर्ण संबंध को और मजबूत करेगी। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और व्यापार, ऊर्जा, कृषि संस्कृति, हवाई सेवा से जुड़ी चर्चा भारतीय नेताओं के साथ उनकी (प्रचंड

की) बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

सवाल है कि जब दौरे में कोई भी विवादित या एकपक्षीय समझौता हुआ ही नहीं, तो नेपाल की विपक्षी पार्टियां इतना तीखा विरोध क्यों कर रही हैं? जब बातचीत के एजेंडा में सीमा विवाद जैसे कड़वे मुद्दे शामिल ही नहीं थे तो नेपाली विपक्षी पार्टियां सीमा विवाद का सवाल क्यों खड़ा कर रही हैं? इस प्रश्न का जवाब खोजने के लिए हमें नेपाल की अंदरुनी राजनीति को समझना होगा। एक जमाना था जब भारत के प्रति रुझान की भावना नेपाली राजनीति और जनमत का अभिन्न हिस्सा थी। लेकिन अब नेपाल की राजनीति में भारत विरोध और भारत समर्थन की दो समांतर धाराएं चलती हैं। बीते वर्षों में नेपाली जनता के एक बड़े समूह में भी भारत विरोधी भावना स्थापित की जा चुकी है। वैसे अब भी मधेश और तराई क्षेत्र के नेपाली लोग भारत के साथ किसी प्रकार का कटु संबंध पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दुष्प्रचार के दम पर कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थकों के मन में बीते वर्षों में यह धारणा बना दी गई है कि भारत नेपाल पर अपना अनावश्यक प्रभुत्व थोपता है। यही कारण है कि प्रचंड समेत अन्य कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि वाले प्रधानमंत्रियों ने हमेशा यह जताने की कोशिश की है कि वे भारत की अपेक्षा चीन के साथ नजदीकी रखना चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने कार्यकाल में सीमा विवाद का मुद्दा बार-बार उछाला। भगवान राम के जन्म को लेकर सवाल खड़े किए। विदेशी महिलाओं की शादी उपरांत नागरिकता से संबंधित कानून को बदल दिया था। इतना ही नहीं, कई प्रधानमंत्रियों ने अपनी प्रथम विदेश यात्रा के लिए चीन का चयन किया जोकि परंपरा के विपरीत था।

यह बात अलग है कि इन सब कवायदों के बावजूद नेपाल को चीन से ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला जिससे उसकी व्यवहारिक आवश्यकताएं पूरी हों। आयात-निर्यात से लेकर, तकनीक, शिक्षा, आवागमन, ऊर्जा, पेट्रोलियम समेत लगभग हर दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेपाल आज भी भारत पर आश्रित है। ऐसे में भारत से संबंध को मैत्रीपूर्ण बनाए रखना नेपाल की मजबूरी है। परंतु विरोध को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टियों को प्रचंड द्वारा उज्जैन में महाकाल की पूजा-अर्चना करना भी पच नहीं रहा है। गौरतलब है कि प्रचंड माओवादी विचारधारा के नेता रहे हैं। जिस माओवादी विद्रोह ने नेपाल में हजारों लोगों की जान ली, उसके वे सर्वेसर्वा रहे हैं। उनकी पार्टी हिंदुत्व का प्रबल विरोध करती रही है। माओवादी विद्रोह के दौरान नेपाल में कई हिंदू विरोधी अभियान चलाए गए थे। स्वयं प्रचंड कभी भी नेपाल स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नहीं गए। अब जब प्रचंड भगवा वस्त्र पहनकर महाकाल मंदिर में मंत्रोचार कर रहे हैं तो कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों को यह बात हजम नहीं हो रही है। यह बात अलग है कि कोई बड़े विरोधी नेता खुलकर इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेपाल में स्थानीय स्तर के नेता इसका तीव्र विरोध कर रहे हैं। विरोध को देखकर प्रचंड ने भी बचाव में अपना सुर बदल लिया है। यात्रा से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने समझौते को ऐतिहासिक महत्व का बताया। लेकिन अब वे कहने लगे है कि सीमा विवाद का मुद्दा भारत के साथ नेपाल के द्विपक्षीय संबंध का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। गौरतलब है कि नेपाल ने साल 2020 में एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गया था। नेपाल के नक्शे में तीन भारतीय क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। इसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रचंड का यह दौरा उनके विगत की दो राजनयिक यात्राओं से अधिक सकारात्मक रहा। वार्ता के एजेंडे व्यवहारिक थे। स्वयं प्रचंड ने यात्रा से पूर्व यह संकेत देने की पूरी कोशिश की कि वे भारत के साथ मधुर संबंधों को बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। उल्लेखनीय है कि प्रचंड ने अपनी यात्रा के महज कुछ घंटे पूर्व विवादित नेपाली नागरिकता कानून को संशोधित करने का विधेयक राष्ट्रपति से मंजूर करवाया। भारत शुरू से इस कानून में संशोधन की मांग करता रहा है। उन्होंने वैचारिक दबाव के बावजूद हिंदुत्व के प्रति अपनी नजदीकी दिखाने की कोशिश की। आखिर क्यों? कई विश्लेषकों का मानना है कि प्रचंड यह सब व्यक्तिगत कारणों से कर रहे हैं। दरअसल, 16 साल पहले नेपाल में हिंसक माओवादी आंदोलन का अंत हुआ, जिसमें 17 हजार लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत की मध्यस्थता से माओवादियों और लोकतंत्र समर्थक दलों के बीच समझौता हुआ था। 2006 में हुए शांति समझौते में कहा गया था कि मानवाधिकार उल्लंघन की जांच होगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। अब इस जांच को आगे बढ़ाने की मांग उठ रही है। इस बात की पूरी संभावना है कि जांच होने पर प्रचंड समेत कई माओवादी नेता इसकी चपेट में आकर जेल जा सकते हैं। नेपाली सुप्रीम कोर्ट भी प्रचंड की भूमिका की जांच कर रहा है। चूंकि यह समझौता संयुक्त राष्ट्र समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उपस्थिति में हुआ था, इसलिए प्रचंड भारत से सहयोग चाहते हैं।

बापू की दिनचर्या

स्वाध्याय और लेखन (भाग-7)

गतांक से आगे...

हम तो कोरा पानी पीने वाले गरीब आदमी हैं! फिर, बापू ने गंभीरतापूर्वक कहा- यहाँ आश्रम में हाथ से बना कागज मिलता है। आज यहाँ कार्ड भी बना है, उस पर लिखो। चतुर्वेदीजी फाउंटेनपेन से लिखनेवाले थे कि बापू ने उनसे फिर पूछा- आप फाउंटेनपेन से कब से लिख रहे हैं? डचगायना वाले भी क्या कहेंगे कि इनके पास घर की कलम भी नहीं! चतुर्वेदीजी बोले- बहुत दिनों से। बापू बोले- पहले अफ्रीका में मैं भी फाउंटेनपेन का प्रयोग करता था । अब कलम से लिखता हूँ। इतना कहकर बापू ने सरकंडे की कलम मँगाई । चाकू से चतुर्वेदीजी ने उसे बनाया और घर की बनी काली स्याही से, हाथ के बने कागज पर बापू का संदेश लिखा। दूसरा प्रसंग दिल्ली की हरिजन बस्ती का है। प्रातःकाल था। बापू कुछ लिख रहे थे। उस समय कस्तूरबा और महादेव भाई के अतिरिक्त वहाँ कोई नहीं था। एक बहन बापू के हस्ताक्षर लेने पहुँचीं। उन्होंने जब हस्ताक्षर पुस्तिका बापू के सामने रखी, तब वे बोले-इस विदेशी एलबम पर मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता। यह सुनकर बहन का दिल बैठ-सा गया। बापू ने उनकी मनःस्थिति पहचान ली। उन्होंने उसे एकाएक हँसकर आत्मीयता के स्वर में कहा- तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हें खद्दर की जिल्द का एलबम दूँगा। उन्होंने खद्दर की जिल्द का छोटा-सा स्वच्छ और सुंदर एलबम मँगवाया। हस्ताक्षर के लिए जब उन बहन ने अपनी फाउंटेनपेन उनकी ओर बढ़ाई तब आत्मीयतापूर्ण भर्त्सना के स्वर में बापू बोले- तुम्हारी यह पेन भी विदेशी है। मैं अपने हस्ताक्षर देशी कलम से करूँगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी की दावात और बाँस की कलम से हस्ताक्षर कर दिया। सेवाग्राम में बापू अपनी कुटिया में गादी पर पालथी मारकर बैठते और फुलस्केप आकार की लकड़ी की एक पटिया अपने घुटने पर रखकर सादे, हलके अखबारी कागज के पैड पर बड़े अक्षरों में लिखते। पास में लकड़ी का छोटा-सा स्टैंड था, जिस पर पेन और पेंसिल रखी जाती। चाकू, कैंची और रबर के लिए लकड़ी की पेटी थी। बापू की कुटिया के पीछे एक कमरे में प्यारेलालजी नैयर, कनु भाई गांधी और टाइपिस्ट परशुराम भाई मेहरोत्रा आदि प्रायः बैठते, जो पीछे के दरवाजे से कार्यवश वहाँ आया-जाया करते। टेलीफोन, फाइलों की आलमारियाँ और टाइपराइटर- ये सब इसी कमरे में थे।

संक्षिप्त समाचार

नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी 10 जून को निकालेंगे रथ यात्रा

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर अब संविदा कर्मचारी रथ यात्रा निकालेंगे। यह रथ यात्रा 10 जून को निकलेगी। इस दौरान कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। यह प्रदर्शन और धरना पूरे प्रदेश में होगा। इसके लिए बुधवार को कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि साढ़े चार साल हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। कर्मचारियों ने कहा कि, सरकार के जन घोषणापत्र में नियमितीकरण का वादा किया गया था। समय-समय पर मुख्यमंत्री भी विधानसभा एवं विभिन्न मीडिया माध्यमों में भी इस संबंध में अपनी सहमति जताई है। सरकार के साढ़े चार साल बीतने के बाद भी नियमितीकरण के संबंध में अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं।

हाइवा ने कई ट्रकों और कार को मारी टक्कर, गाड़ियों से दबे लोग, कई घायल

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाजार जिले में बुधवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया है। भाटापारा बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार हाइवा ने कई वाहनों की अपनी चपेट में ले लिया। हाइवा की टक्कर से चार मालवाहक और एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में कई लोग गाड़ियों के बीच में और नीचे दबे हुए हैं। हादसा होते देख आसपास के लोगों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें दो की हालत गंभीर है।

स्वास्थ्य अधिकारी के अस्थाई पदस्थापना के लिए काउंसिलिंग 12 को

महासमुन्द। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत महासमुन्द में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के अस्थाई पदस्थापना हेतु काउंसिलिंग 12 जून 2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुन्द के प्रशिक्षण कक्ष ऊपर तल में आयोजित की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवँ स्वास्थ अधिकारी ने बताया कि काउंसिलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं सूचना जिले की वेबसाईट में अपलोड किया गया है तथा कार्यालय के सूचना पटल में भी चस्पा किया गया है।जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि शराबबंदी का आदेश देने में समय नहीं लगेगा

रायपुर। बिलासपुर में आयोजित कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में शराबबंदी का आदेश देने में समय नहीं लगेगा, लेकिन शराबबंदी के असर को सोचना पड़ेगा, इसके लिए समाज में वातावरण बनाना पड़ेगा। प्रदेश में शराबबंदी नहीं, पूरी तरह नशाबंदी हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिससे किसी की जान जाए।

चार जिंदा मोर, तेंदुआ, भालू और बाघ के खाल के साथ 6 गिरफ्तार

गरियाबंद। गरियाबंद वन विभाग की टीम ने 6 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से बाघ की खाल, चार जिंदा मोर तथा बड़ी मात्रा में तेंदुआ, भालू, मोर के अवशेष बरामद किए हैं। इसके अलावा वन विभाग की टीम ने शिकार में इस्तेमाल किए गए हथियार भरमार बंदूक, तीर-कमान, जाली, बरामद किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़-ओडिशा की बार्डर पर एंटी पोचिंग टीम उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद एवं वन परिक्षेत्र खरियार ओडिशा के स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

मौसम विभाग का अलर्ट, 11 जिलों में गर्म हवा की चेतावनी

रायपुर। इस वर्ष गर्मी ने पारा राजधानी में 43 से ऊपर नहीं जा पाया लेकिन गर्मी ने अपने अंतिम चरण में जो तेवर दिखाएं है उससे सामान्य जीवन पर खासा असर पड़ा और लोग हवाकर करने लगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए आगामी 48 घंटों में सूबे के 11 जिलों में गर्म हवा चलने की चेतावनी दी है। मानसून अगले 48 घंटों में केरल में पहुंचने की संभावना भी विभाग ने जताई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 24 घंटे में जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, महासमुंद, मुंगेली, बलौदाबाज़ार, कांकेर (पश्चिम), राजनांदगाँव, रायपुर, दुर्ग और बेमेतरा जिलों के एक-दो स्थानों में ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बनने की संभावना जताई है।

राज्य में 23.30 लाख से अधिक परिवारों को मिला घरेलू नल कनेक्शन

रायपुर। राज्य के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अब तक 23 लाख 30 हजार 317 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ राज्य के 43 हजार 971 स्कूलों, 41 हजार 692 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 17 हजार 290 ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। जिसमें छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सर्वाधिक 2 लाख 3 हजार 755 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में सबसे आगे है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिटफंड घोटाले में लगातार हो रही है कार्रवाई

निवेशकों को अब तक 33.44 करोड़ की धनराशि वितरित, पैसा वापस दिलाने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनियों) एवं उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रकाई की जा रही है जिसके फलस्वरुप पीड़ितों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। अधिक ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा दी थी। अब उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है क्योंकि ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पश्चात् सरकार ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को राशि लौटाई है। देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दिला रहा है। चिटफंड कंपनियों की नीलामी से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है।

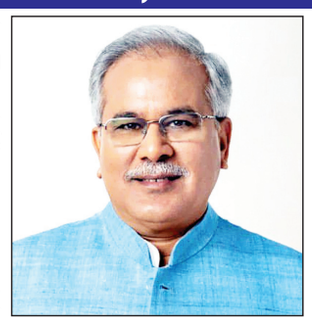

चिटफंड के दर्ज प्रकरण की जानकारी

छत्तीसगढ़ में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 465 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। 401 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। 06 प्रकरण में खात्मा और 03 प्रकरण में खारजी हुई है। 55 प्रकरण पुलिस में विवेचनाधीन है। दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर्स व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की सम्पत्तियों की नीलामी, वसूली, राजीनामा से 55 करोड़ 98 लाख 90 हजार 866 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

चिटफण्ड के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति

जिला दण्डाधिकारी कार्यालयों में कुल 25 लाख 68 हजार 05 आवेदन पत्र जमा किये गये है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 4 लाख 54 हजार 324 आवेदन पत्र निराकृत हो गए हैं, शेष 20 लाख 95 हजार 407 आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पीड़ितों की धन वापसी की स्थिति

46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपये की धनराशि निवेशकों को वितरित की गई है। 29 प्रकरणों में 21 कंपनियों से 22 करोड़ 54 लाख 13 हजार 123 रुपये की राशि सरकारी खाते में जमा है जिनके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 31 प्रकरणों में 17 कंपनियों की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 24 करोड़ 82 लाख 30 हजार 233 रुपये की न्यायालय के अंतिम आदेश उपरांत नीलामी कार्यवाही कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। 95 प्रकरणों में कुल 80 करोड़ 81 लाख 21 हजार 99 रुपये की सम्पत्ति की कुर्की का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। 137 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678 करोड़ 68 लाख 63 हजार 423 रूपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 116 करोड़ 63 लाख 95 हजार 262 रुपये तथा राज्य के बाहर 562 करोड़ 04 लाख 68 हजार 161 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश हेतु कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है।

इसी तरह से 51 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 138 करोड़ 95 लाख 68 हजार 986 रुपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 107 करोड़ 99 लाख 31 हजार 586 रुपये तथा राज्य के बाहर 30 करोड़ 96 लाख 34 हजार 400 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतिम आदेश हेतु माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।

उद्योग मंत्री लखमा ने निर्माणाधीन इथेनॉल प्लांट का किया निरीक्षण

रायपुर। उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने आज कोण्डागांव जिले के ग्राम कोकोडी में निर्माणाधीन इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा की। चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वे सभी प्लांट के निर्माण के प्रति उत्साहित हैं। प्लांट की निर्माण तेज गति को देखते हुए सभी आश्वस्त है कि अब उनके मक्के की फसल का उचित मूल्य प्राप्त होगा और उन्हें लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि लगभग 140 करोड़ रूपए की लागत से कोकोड़ी में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

उद्योग मंत्री ने इस मौके पर उन्होंने कलेक्टर श्री दीपक सोनी के साथ प्लांट का भ्रमण करते हुए प्लांट निर्माण से जुड़े अधिकारियों से चर्चा कर प्रगति के संबंध में जानकारी ली, अधिकारियों ने बताया कि प्लांट का कार्य निर्माण का कार्य दुरुत गति से संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री सोनी ने बताया कि प्लांट शुरू होने पर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर प्लांट में उनकी क्षमतानुसार कार्य प्रदान किया जाएगा और आस पास के ग्रामीणों को रोजगारमूलक गतिविधियों से लाभान्वित किया जायेगा।उद्योग मंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि इस प्लांट के खुल जाने से क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सुलभ होगा। उन्होंने प्लांट में कार्यरत श्रमिकों से नियमित मजदूरी भुगतान एवं कार्य की परिस्थितियों की जानकारी दी। श्रमिकों ने बताया कि प्लांट में नियमित रूप से भुगतान हो रहा है, साथ ही अधिकारियों द्वारा कार्य में पूर्ण सहयोग दिया जाता है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रेम प्रकाश शर्मा, प्लांट प्रबंध निर्देशक केएल उइके सहित प्लांट निर्माण से जुड़े एजेंसियों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

गिरिराज सिंह 8-9 जून को बस्तर प्रवास पर रहेंगे

जगदलपुर। भाजपा के केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 8 व 9 जून को बस्तर संभाग के प्रवास पर रहेंगे। वे गुरुवार 09 जून को जगदलपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। श्री सिंह दंतेवाड़ा, कांकेर और केशकाल भी जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बुधवार को कांकेर में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। वे कांकेर में ही रात्रि विश्राम करेंगे, 9 जून को सुबह 10.30 बजे वे केशकाल में आकाश मेहता के निवास पर जाएंगे। वहां से दोपहर 12 बजे रवाना होकर केंद्रीय मंत्री सिंह जगदलपुर आएंगे। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्थित टाउन हाल क्लब मैदान पर दोपहर 2 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। शाम को वे यहां जिला भाजपा कार्यालय में संभाग व जिला स्तर के पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे। जगदलपुर में रात्रि विश्राम के बाद मंत्री गिरिराज सिंह 9 जून को सुबह दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, जहां मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करने के बाद वे जिला प्रशासन के अपने विभाग से संबंधित अधिकारियों की बैठक लेंगे। दोपहर 12 से 1.30 बजे तक मंत्री श्री सिंह जिला प्रशासन द्वारा आयोजित केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की बैठक में शामिल होंगे। लंच के बाद वे दंतेवाड़ा के जावंगा स्थित एजुकेशन हब का जायजा लेंगे। शाम को वे जगदलपुर लौट आएंगे। यहां शाम 4.30 बजे मंत्री गिरिराज सिंह जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करेंगे। रात 7.30 बजे वे सद्भावना भवन बस्तर पहुंचेंगे, जहां बस्तर क्षेत्र के नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से चर्चा उपरांत गिरिराज सिंह कांकेर जाकर रात्रि विश्राम करेंगे। 10 जून को सुबह रायपुर पहुंचकर वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

प्रदेश प्रभारी चंदन दुर्ग में लेंगे संभागीय सम्मेलन

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी डॉ. चंदन यादव 8 जून 2023 गुरूवार को सुबह 10 बजे रायपुर से दुर्ग के लिये रवाना होंगे। सुबह 11 बजे दुर्ग के चौहान एम्पीरियल, स्टील कॉलोनी में आयोजित संभागीय सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम 5 बजे दुर्ग से रायपुर के लिये रवाना होंगे।

21 जून को समारोह पूर्वक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। प्रदेश के शहरों और गांवों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके माध्यम से हर घर आंगन योग के संदेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु आवश्यक तैयारियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य शासन के विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निकायों एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से आवश्यक समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अपर संचालक श्री पंकज वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ योग-आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरों और गांवों के प्रमुख स्थल पर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी के साथ सामूहिक योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 मनाने के लिए सामान्य योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) के प्रदर्शन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी और वृद्धाश्रम, सार्वजनिक उपक्रमों, शासन के सभी विभागों के प्रमुख स्थानों में भी योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा योग के संबंध में जन-जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। अस्पताल, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन जैसे सार्वजनिक संस्थान पर और पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम आदि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बैनर प्रदर्शित किए जाएंगे।

राज्य शासन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु आवश्यक तैयारियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य शासन के विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निकायों एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से आवश्यक समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अपर संचालक श्री पंकज वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मानसून के 9 दिनों की देरी से 24 तक बस्तर पहुंचने की संभावना

जगदलपुर। बस्तर संभाग में नौतपा के खत्म होने के बाद छुट-पुट बारिश होने से उमस बढ़ गई है। गर्मी से तो लोगों को राहत है, लेकिन अब लोग उमस से राहत के लिए मानसून का इंतजार करने लगे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 जून तक केरल पहुंचने वाला मानसून 7 जून तक नहीं पहुंच पाया है, ऐसे में बस्तर के मार्ग से होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले मानसून में देर होगी। वहीं अगले 1 दिन बाद केरल तक मानसून पहुंचने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। ऐसे में 24 जून तक मानसून बस्तर पहुंच सकता है। यदि 24 जून तक मानसून बस्तर पहुंच जाता है तो इस वर्ष 9 दिनों की देरी से पहुंचेगा।

ज्ञात हो कि केरल से मानसून को बस्तर पहुंचने में 16 दिनों का समय लगता है, वहीं मानसून के केरल पहुंचने के 16 दिनों बाद ही मानसूनी हवाएं बस्तर पहुंचेंगी। इन हालातों में फिलहाल मानसून की बस्तर में दस्तक के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि इस वर्ष मानसून को केरल पहुंचने में खासी देर हुई है। अमूमन 31 मई या 1 जून तक मानसून केरल पहुंच जाता है, जिसके 16 दिनों बाद मानसून बस्तर पहुंचता है। कई बार मानसूनी हवा के तेज होने से समय से पहले भी मानसून पहुंच जाता है। उन्होने बताया कि 24 जून तक मानसून बस्तर में दस्तक देने की संभावना है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून में देरी से बस्तर के किसान चिंतित

बस्तर संभाग के अधिकांश किसान मानसून के भरोसे खेती-किसानी करते हैं, क्योंकि बस्तर में सिंचाई के साधन की कमी है, इसलिए किसान 15 जून के पहले-पहले धान की बोआई कर लेते हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में किसान धान बोआई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है, कि 15 जून के आस-पास तक मानसून बस्तर में दस्तक दे देगा और बारिश होगी। कई किसानों ने धान बोआई पूरी कर अब अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अच्छी बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के देर में आने की खबर से बस्तर के किसान चिंतित हैं। बस्तर में दक्षिण-पश्चिम मानसून पहुंचने के सप्ताहभर पहले से ही प्री मानसून की बारिश होती है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक मानसून की गति को काफी धीमी बता रहे हैं।

सीएम की अधिकारियों को दो टूक, पटवारी हड़ताल से आमजनों को न हो परेशानी

रायपुर। विगत 15 मई से हड़ताल कर रहे पटवारियों के चलते अब शासकीय कामकाज भी चरमराने लगा है। इसे लेकर कल ही मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए आला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि काम प्रभावित न हो और आमजनों का काम प्रभावित न हो। ज्ञात हो कि पटवारियों के हड़ताल के चलते सबसे ज्यादा परेशानी युवा वर्ग को हो रही है। इसके बाद आम मध्यमवर्गीय परिवारों को भी भारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। युवा वर्ग और छात्र वर्ग जहां नए शिक्षण सत्र में प्रवेश लेने के लिए आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहे हैं तो वहीं युवा वर्ग को भी कालेजों में प्रवेश के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है। यह दस्तावेज पटवारियों के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। आय, जाति और मूल निवास जैसे दस्तावेज नहीं बन पाने के लिए छात्र और युवा वर्ग खासे बेहाल हैं। इसी तरह वर्तमान में जमीन-खरीदी-बिक्री के बाद नामांतरण, सीमांकन और भुईयां जैसे शासकीय पोर्टल में नाम दर्ज कराने के लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। पटवारियों के इस हड़ताल से राजस्व प्रभावित हो रहा है। इससे अलावा विभागीय कामकाज भी बुरी तरह से चरमरा गया है।

पटवारियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री ने जतायी नाराजगी

छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल से आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि हड़ताल की वजह से युवाओं, नागरिकों को नौकरी,भत्ते संबंधी कार्यों में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 23 दिन से पटवारियों की हड़ताल चल रही है जिससे कई सारे कामकाज प्रभावित हो रहे हैं,मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद संभवतः कार्रवाई की प्रशासनिक चेतावनी मिल सकती है।

प्रेक्षक हैं निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि : आयुक्त ठाकुर राम सिंह

■ निर्वाचन प्रेक्षकों को वीसी के ज़रिये दी गई जानकारी

रायपुर। नगरपालिकाओं और त्रि स्तरीय पंचायतों के आम और उप निर्वाचन 2023 के लिए नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षकों की छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई। दोपहर साढ़े 12 बजे से आहुत इस बैठक में निर्वाचन प्रेक्षक के तौर पर नियुक्त अधिकारियों को उनकी भूमिका, दायित्व और अधिकार इत्यादि के विषय में विस्तार से बताया गया।

इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह ने वीसी को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग प्रेक्षकों की नियुक्ति करता है। अतः यह प्रेक्षक आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने सबको उत्साहित करते हुए कहा कि बिना तनाव के, लेकिन गंभीरता से अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने ज़ोर दिया कि प्रेक्षक के तौर पर नियुक्त अधिकारी सुनिश्चित करें कि नगरीय निकाय और पंचायत के जिस क्षेत्र में निर्वाचन होना है वहाँ आदर्श

आचरण संहिता सही तरीक़े से लागू हो। निर्वाचन से संबंधी अगर कहीं कोई शिकायत हो तो उसका निराकरण करने का प्रयास भी करें। जहां नगर पालिकाओं का चुनाव होना है वहाँ राजनैतिक दलों की बैठक में प्रेक्षक भी मौजूद रह सकते हैं। बैठक में आयुक्त श्री सिंह ने आयोग की पहल व्छछव् (ओएनएनओ-ऑनलाईन नॉमिनेशन) और जाबो के बारे में भी जानकारी दी जिससे अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने प्रोत्साहित हों।

सचिव श्री मोहम्मद अब्दुल कैसर हक ने कहा कि स्थानीय निर्वाचन सुदृढ़ तरीके से हो इसके लिए सभी प्रेक्षक अच्छे से काम करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी प्रेक्षक अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करेंगे। यह भी कहा कि यदि निर्वाचन संपन्न कराने में कोई दिक्कत आती है तो आयोग से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं।

बैठक में अवर सचिव श्री आलोक श्रीवास्तव ने प्रेक्षक की भूमिका, दायित्व और अधिकार से सबको अवगत कराया। इसमें अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिला, संविक्षा, प्रतीक आवंटन, प्रचार काल में प्रेक्षक की भूमिका और दायित्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसी तरह मतदान पूर्व निर्वाचन प्रबंधन, मतदान दिवस का प्रबंधन के टिप्स दिये गये। साथ ही मतगणना में प्रेक्षकों की भूमिका और नगर पालिका और त्रि स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए भेजे जाने वाले प्रतिवेदन के विषय में भी बताया गया।

नगर पालिका निर्वाचन के लिए पाँच प्रतिवेदन भेजना होगा

ज्ञात हो नगर पालिका के निर्वाचन में नियुक्त प्रेक्षक द्वारा आयोग को पाँच प्रतिवेदन भेजे जाएँगे। पहला संविक्षा के तुरंत बाद, दूसरा अभ्यर्थिता वापसी और प्रतीक आवंटन के बाद, तीसरा प्रतिवेदन मतदान के दो दिन पहले भेजा जाना होगा। चौथा प्रतिवेदन मतदान के तुरंत बाद और पाँचवा प्रतिवेदन मतगणना के फौरन बाद भेजना होगा।

पंचायत निर्वाचन के लिए प्रतिवेदन

इसी तरह त्रि स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में तैनात प्रेक्षक कुल पाँच प्रतिवेदन आयोग में भेजेंगे। पहला नामांकन प्रक्रिया के दौरान, दूसरा प्रतीक आवंटन के बाद, और तीसरा मतदान के दो दिन पहले भेजेंगें। इसके अलावा चौथा मतदान के दिन शाम या फिर मतदान के दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक और पाँचवा और आखिरी प्रतिवेदन सारिणीकरण/परिणाम घोषणा के फ़ौरन बाद भेजना होगा।निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी भी प्रेक्षकों को दी गई। इस अवसर पर श्री अवनीश शरण, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, श्री जगदीश सोनकर संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, श्री डी. राहुल वेंकट, उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, आयोग के उपसचिव द्वय श्री दीपक अग्रवाल, श्रीमती अंकिता गर्ग सहित आयोग के अधिकारी उपस्थित रहे।

नौ साल गरीब कल्याण को समर्पित : साव

धान समेत तमाम फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि पर मोदी जी का अभिनंदन

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के नौ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार विशेष जनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून के बीच चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सयुंक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए भाजपा के विधानसभा स्तरीय सयुंक्त मोर्चा सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मोदी सरकार की नौ साल की उपलब्धियां गिनाईं। कहा कि, मोदी सरकार के नौ साल गरीब कल्याण को समर्पित हैं। उन्होंने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाईं और उस तक पहुंचाई। सांसद अरुण साव आज को दो दिवसीय बस्तर प्रवास के तहत दंतेवाड़ा पहुंचे थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार आज तक के भारत के इतिहास में और विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार गरीब ,शोषित ,वंछित, दलित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग एवं आदिवासियों के उत्थान के प्रति समर्पित सरकार है। साव ने कहा की आधुनिक भारत के विकास के स्वर्णिम पल का इतिहास रचा जा रहा है।

आज भारत तेजी से मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के शक्तिशाली देशो को पछाड़ कर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी एक मात्र ऐसे नेता है जो भारत के गरीब एवं वंछित जनता की पीड़ा को परिवार के सदस्य के तरह महसूस करते हैं। केंद्र सरकार की योजनाये गरीब कल्याण को समर्पित है। इससे पहले साव किरन्दूल पहुंचे और माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुए।

बढ़े हुए कीमत का सारा लाभ सीधे किसानों को दे भूपेश सरकार

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज धान सहित कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी वृद्धि के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री साव ने कहा कि अन्नदाता के सम्मान का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री लगातार समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि दी जा रही है ताकि किसानों को अतिरिक्त राशि मिल सके। भारत की कृषि के विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री हमेशा तत्पर रहते हैं।प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि बिना किसी बहाने के बढ़ी हुई कीमत का पूरा लाभ किसानों को सीधे पहुचाने की व्यवस्था भूपेश सरकार को करना चाहिए। धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि का व्यापक लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि तुअर दाल, उड़द दाल, धान और मक्के का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। तुअर दाल में 400 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि हुई है। उड़द दाल में 350 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद समर्थन मूल्य 6950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मक्के में 128 रुपए प्रति क्विंटल और धान का समर्थन मूल्य 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।

23 आईएएस के तबादले 2 कलेक्टर बदल

- संजय अलंग रायपुर, भीम सिंह बिलासपुर कमिश्नर बनाए गए, चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल
- महानदी भवन से ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए हैं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। संजय कुमार अलंग को बिलासपुर की जगह रायपुर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। आईएएस भीम सिंह को बिलासपुर संभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है इधर सिद्धार्थ कोमल परदेशी को सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि प्रसन्ना आर को स्वास्थ्य सचिव के प्रभार से मुक्त किया गया है। भुवनेश यादव को पीडब्ल्यूडी का सचिव बनाया गया है।

आकाश छिकारा को गरियाबंद जिला का कलेक्टर बनाया गया है और महासमुंद कलेक्टर की जिम्मेदारी प्रभात मलिक को दी गई है। इसके अलावा रानू साहू, जयप्रकाश मौर्य, शिखा राजपूत, केडी कुंजाम, सारांश मित्तर, रितेश अग्रवाल, रणबीर शर्मा और नीलेश क्षीरसागर समेत 23 आईएएस अधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है।

हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग, मोबाइल पर मिल रहा है अलर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए एआई आधारित 'छत्तीसगढ़ एलीफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट एप' विकसित किया गया है। पिछले 3 महिनों से उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व में इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। 10 किलोमीटर के इलाके में हाथियों के रियल टाईम मूवमेंट का अलर्ट ग्रामीणों के मोबाइल पर सफलतापूर्वक भेजा रहा है। इस एप में ग्रामीणों के मोबाइल नंबर और जीपीएस लोकेशन का पंजीयन किया जाता है। जब एलीफैंट ट्रैकर्स द्वारा हाथियों के मूवमेंट का इनपुट एप पर दर्ज किया जाता है, तो एप द्वारा स्वचालित रूप से ग्रामीणों के मोबाइल पर अलर्ट जाता है।
छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) और वन्यजीव विंग द्वारा संयुक्त रूप से इस एप को विकसित किया गया है। यह एप एलीफैंट ट्रैकर्स (हाथी मित्र दल) से प्राप्त इनपुट के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर काम करता है। इस एप का उद्देश्य हाथी ट्रैकर्स द्वारा की जाने वाली 'मुनादी' के अलावा प्रभावित गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल पर कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप अलर्ट के भेजकर हाथियों की उपस्थिति के बारे में सूचना पहुंचाना है।

वर्तमान में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व (गरियाबंद, धमतरी) के लगभग 400 ग्रामीणों को इस अलर्ट सिस्टम में पंजीकृत किया गया है और पिछले 3 महीनों से यह काम कर रहा है। अन्य वन प्रभाग भी एप का उपयोग कर सकते हैं और अपने संबंधित ग्रामीणों को पंजीकृत कर सकते हैं। एप को वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) और वन्यजीव विंग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सिहावा विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव द्वारा इकोपार्क मेचका, यूएसटीआर में एप को लॉन्च किया जाएगा।

हाथी मित्र दल के सदस्य हाथियों के स्थान, झुंड के नाम, व्यवहार और अन्य विशेषताओं को फीड करने के लिए क्वज्ञ एप (ओपन सोर्स) का उपयोग करते हैं। यह क्वज्ञ एप ऑनलाइन मोड (रियल टाइम) और ऑफलाइन मोड (करीब-रीयल टाइम जब ट्रैकर मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होते हैं) दोनों में काम करता है।

रायपुर ननि ने शुरू किया RRRe- Make कैंपेन

रायपुर। विश्व पर्यावरण दिवस पर रायपुर नगर निगम ने अनुपयोगी सामग्रियों से उत्कृष्ट कलाकृति तैयार करने वाले शहर के कलाकारों को प्रेरित करने 'ट्रिपल आर. बेस्ट ऑफ द वेस्ट कैंपेन शुरू किया है. इसके तहत आम नागरिकों से 15 जून तक ऐसी कलाकृति तैयार कर इसके छायाचित्र और शॉर्ट वीडियो रायपुर नगर निगम को भेजने का अनुरोध किया गया है. चयनित उत्कृष्ट कलाकृतियों व संरचनाओं को नगर निगम अपने उद्यान और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित कर इन कलाकारों को सम्मानित करेगा.रायपुर नगर निगम के जरिये शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने अपने प्रयासों में जन सहभागिता को बढ़ावा दे रहा है. इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी होगी और शहर विकास में उत्तरदायित्व के साथ सभी आयु वर्ग अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे. पूर्व में कचरा महोत्सव, रोको-टोको, ट्रिपल आर. सेंटर, नो प्लास्टिक कैंपेन जैसे कार्यक्रमों में स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों ने सकारात्मक भूमिका निभाई हैं।

हांगकांग में बेसबाल का हुनर दिखाकर अब कनाडा रवाना होगी अंजली

- बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की एक छोटे से गांव से निकलकर इंडियन बेसबाल टीम में जगह की पक्की*
- सहयोग के लिए शासन-प्रशासन का किया आभार व्यक्त

रायपुर। जब आपके अंदर कुछ कर गुजरने को जुनून हो तो मुश्किल परिस्थितियां भी हौसलों को डिगा नहीं पाती और सफलता एक ना एक दिन आपके कदम जरूर चूमती है। इसे साबित किया है बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम सिविलदाग में रहने वाली अंजली खलखो ने। आज वह अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बदौलत इंडियन बेसबाल टीम से खेलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। अंजली ने हाल ही में हांगकांग में आयोजित वूमेंस एशिया बेसबॉल चौम्पियनशिप में इंडियन टीम का हिस्सा रहीं। जिसमें इंडियन टीम एशिया लेवल पर 06 वें स्थान पर रही। अंजली आगामी दिसम्बर माह में कनाडा में होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगी।

अंजली खलखो की प्रतिभा को पहचानते हुए समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सहयोग और अवसर प्रदान किया गया। सिविलदाग कुसमी विकासखण्ड का एक छोटा सा गांव है। किसान श्री रिजू खलखो एवं महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारी श्रीमती राजमणी खलखो की पुत्री अंजली बताती है कि उसने कक्षा 6 वीं से ही बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया था। अपनी उपलब्धि का श्रेय उन्होंने अपने परिवार, कोच श्री अख्तर खान, अपनी र्स्पोटस् टीचर सुश्री हेमलता को देते हुए कहती हैं कि सभी ने बचपन से उन्हें खेलने के लिए लगातार प्रेरित किया है। अंजली कहती हैं कि उनके वर्तमान उपलब्धियों में उनके पारिवारिक सहयोग के साथ-साथ छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने शासन-प्रशासन से सहयोग के लिए गुहार लगाई। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। जिसके कारण वे आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं।

अंजली की प्राथमिक शिक्षा लरंगी और रातासिली जैसे शासकीय प्राथमिक शालाओं से हुई है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मोदी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने में असफल : मरकाम

रायपुर। मोदी सरकार के द्वारा धान और रवि फसल के समर्थन मूल्य में की गई मामूली वृद्धि को किसानों के साथ धोखा और छल करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में मात्र 7 प्रतिशत की वृद्धि कर आमदनी दोगुनी होने का इंतजार कर रहे किसानों के ऊपर वज्र प्रहार किया है।किसानों को आर्थिक तंगहाली की ओर ढकेला है।जहाँ एक ओर महंगाई आसमान छू रही है। डीजल पेट्रोल के दाम में 820 प्रतिशत की बढोत्तरी कृषि मजदूरी में 9 से में दोगुनी हुई,कृषि यंत्र और रासायनिक खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर पार्ट्स, ऑयल ग्रीस के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई और फसल बीमा की प्रीमियम में बढ़ोतरी के चलते कृषि लागत मूल्य 2014 के पहले के मुकाबले आज दोगुना हुआ है। वही मोदी सरकार 9 साल में धान के समर्थन मूल्य में बढ़ी हुई लागत मूल्य के एक चौथाई भी बढ़ोतरी नहीं कर पाई है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देशभर के किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देना एवं 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था जो 9 साल में पूरा नहीं हो पाया है।

राम नकारने वाले रामायण महोत्सव करा रहे, अब आई याद : सरोज पांडेय

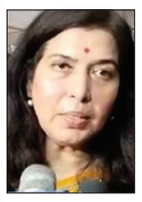

रायपुर। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने रामायण महोत्सव के लेकर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। सांसद पांडेय ने कहा कि, कांग्रेस पूरी तरह से वोट की राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने रामायण महोत्सव के लेकर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। सांसद पांडेय ने कहा कि, कांग्रेस पूरी तरह से वोट की राजनीति कर रही है। जो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। भगवान श्रीराम को नकार रहे थे, वही अब श्री राम जी का महोत्सव करवा रहे हैं। साढ़े चार सालों से सरकार को श्री राम की याद नहीं आई। अब चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस को श्री राम की याद आ रही है। सांसद सरोज बुधवार को मीडिया से बात कर रही थीं। सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी जिसने श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। जो यह सवाल कर रहे कि भगवान श्रीराम है या नहीं। बीजेपी ने कोर्ट में केस लड़ा। लम्बे समय बाद बीजेपी के कारण ही श्री राम मन्दिर की स्थापना अयोध्या में हो रही है। आज चुनाव करीब है तो सीएम भूपेश को श्री राम की याद आ रही है। कांग्रेसियों को माता कौशल्या की याद आ रही है। सीएम के परिवार के लोग भगवान राम को गाली देते हैं। भगवान राम के नाम पर यदि वोट चाहिए तो राम आपके हो गए।

आर्थिक सामाजिक न्याय कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता है : धनंजय

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार जनगणना नहीं करवा कर देश के वंचित लोगो के साथ अन्याय कर रही है। जनगणना कार्यक्रम से सरकारी योजनाओं के जो वास्तविक हितग्राही हैं उनके आंकड़े सामने आएंगे और जो हितग्राही जनगणना नहीं होने के कारण योजना का लाभ लेने से वंचित थे उन्हें योजनाओं का लाभ मिलेगा। मोदी सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हर 10 साल में होने वाले जनगणना को रोके रखी हुई है जनगणना होने से मोदी सरकार की नाकामी सामने आएगी, लेकिन मोदी सरकार देश की पहली और इकलौती सरकार है जो अपनी नाकामी पर पर्दा डालने इरादतन, षडयंत्र पूर्वक आंकड़े छुपाने का काम कर रही है और इसी के चलते राष्ट्रीय जनगणना की अपनी जिम्मेदारियों से केंद्र की मोदी सरकार भाग रही है। केवल जनगणना ही नहीं एनएसएसओ सहित तमाम केंद्रीय एजेंसियां विगत 9 वर्षों से मोदी सरकार के कुशासन पर पर्दा डालने, केंद्र सरकार के दबाव में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, वर्तमान आर्थिक नीतियों की जमीनी हकीकत और वास्तविक स्थिति को लेकर तमाम आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है।

ईडी-आईटी से वे लोग परेशान हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का पैसा लूटा है: सुनील सोनी

रायपुर। सांसद सुनील सोनी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ईडी को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि ईडी और आईटी से वो लोग परेशान हैं, जिन्होंने भ्रष्ट रास्ता अपनाया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का पैसा लूटा है. ये सब एजेंसियां इसलिए बनाई गई हैं, जो पैसे लूटने वाले का पैसा निकाले और उस पैसे से विकास के काम करे.

सांसद सुनील सोनी ने कहा कि श्रष्ठ-द्वझ की कार्रवाई से सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री तिलमिला रहे हैं. मुख्यमंत्री 2-3 बार बयान दर्ज कर चुके हैं, ये आश्चर्य की बात है. इसके साथ ही शराब बंदी को लेकर सरकार के पक्ष को लेकर सांसद ने कहा कि जब गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए थे, तब सर्वे नहीं किया था क्या? उस समय वोट चाहिए था.

सुनील सोनी ने कि मुख्यमंत्री 3-4 बार शराब के संदर्भ में बयान दे चुके हैं, उनको रात में माता-बहन दिखती है, जो कहती हैं कि वोट नही देंगे. शराबबंदी नहीं होगी, तो वोट के लाले पड़ जाएंगे. चुनाव एक उत्सव होता है, लोगों की उम्मीद है नेता ने संकल्प लिया तो पूरा करेगा, जब सपना पूरा नहीं होता तो जनता किनारा कर लेती है.

पटवारियों की हड़ताल खत्म नहीं करा रही सरकार : चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आंदोलनरत पटवारियों की आईडी ब्लॉक किए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले को तानाशाही का परिचायक बताया है। श्री चंदेल ने कहा कि प्रदेश सरकार पटवारियों के नेतृत्व से बातचीत करके आंदोलन का समाधान निकालने के बजाय उसे उलझा रही है, जो प्रदेश सरकार के संवेदनहीन होने का प्रमाण है। नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आंदोलित कर्मचारियों के साथ प्रदेश सरकार ऐसा बर्ताव करे, जैसा साढ़े चार हजार पटवारियों की आईडी ब्लॉक करके प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया है। पटवारियों का आंदोलन 23 दिनों से चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार को इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि वह पटवारियों के नेतृत्व से चर्चा करके इस आंदोलन का समाधान निकाले। श्री चंदेल ने कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पटवारियों के साथ जिस तरह बेरुखी के साथ पेश आ रही है, उसकी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। पटवारियों की न्यायसंगत मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस आंदोलन को समाप्त करके का इरादा प्रदेश सरकार का नहीं है, ऐसा इसके ताजा फैसले से जाहिर हो रहा है। पटवारियों का आंदोलन लंबा खींचने के लिए प्रदेश सरकार को कभी माफ नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस आंदोलन के चलते एक ओर किसानों को अपने राजस्व संबंधी काम और प्रकरणों को निपटाने में परेशानी हो रही है।

महिलाओं के लिए 30 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं

- हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि वर्टिकल आरक्षण 50 फीसदी अनारक्षित और 50 फीसदी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है। एससी, एसटी और ओबीसी को वर्टिकल आरक्षण का लाभ दिया जाता है, और शारीरिक रूप से दिव्यांगों को होरिजेंटल आरक्षण का लाभ दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ष्ट्तक्क्रस्ष्ट 2014 की जारी मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका को निरस्त कर दिया है। याचिका एक महिला अभ्यर्थी की ओर से लगाई गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, महिलाओं के लिए 30 फीसदी से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने फैसले में वर्टिकल और होरिजेंटल आरक्षण के नियम को नए सिरे से स्पष्ट किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच में हुई।

महिला का पद आरक्षित नहीं था

पीएससी ने वर्ष 2014 में राज्य प्रशासनिक सेवा के विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें डिप्टी कलेक्टर के 21 पद शामिल थे। 21 पदों में से 9 पद अनारक्षित, 2 पद एससी, 7 पद एसटी और 3 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थे। इसमें से महिला आरक्षण के तहत 2 पद अनारक्षित महिला और 2 पद एसटी वर्ग की महिला प्रतिभागी के लिए आरक्षित थे। विज्ञापन के अनुसार ओबीसी महिला के पद आरक्षित नहीं थे।

अभ्यर्थी के चयन को दी चुनौती

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट में 10वें नंबर पर ओबीसी वर्ग के प्रतिभागी ओंकार यादव का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। इसे पीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल रही हिमशिखा साहू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कहा कि ओबीसी महिला के लिए पद आरक्षित होने पर उनका चयन यादव की जगह होना था। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया था।

मेरिट लिस्ट में ही नहीं था

इस बीच यादव ने जीएसटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया। वे वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। मामले पर सुनवाई के दौरान बताया गया कि महिला मेरिट में 29वें नंबर पर थी। मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं था। ऐसे में उन्हें याचिका दाखिल करने का भी अधिकार नहीं था। वहीं पीएससी की तरफ से जानकारी दी गई कि नियमों का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए उनके पक्ष में जारी अंतरिम आदेश निरस्त कर दिया।

सभी लाभ देने के आदेश दिए

कोर्ट ने प्रतिवादी अधिकारी की कोई गलती नहीं होने के कारण सीनियारिटी समेत अन्य लाभ देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य के फैसलों का हवाला देते हुए वर्टिकल, होरिजेंटल आरक्षण को स्पष्ट किया है। कहा है कि वर्टिकल आरक्षण 50 फीसदी अनारक्षित और 50 फीसदी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है। एससी, एसटी और ओबीसी को वर्टिकल आरक्षण का लाभ दिया जाता है, और शारीरिक रूप से दिव्यांगों को होरिजेंटल आरक्षण का लाभ दिया जाता है।

हड़ताली पटवारियों को तगड़ा झटका राज्य सरकार ने लगाया ईएसएमए

- अत्यावश्यक सेवा संधारण को देखते हुए शासन ने पटवारियों के कार्य करने से इंकार किये जाने का किया प्रतिषेध

रायपुर। विगत 15 मई से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते आम जनता के राजस्व संबंधी कार्यों के निपटारे में काफी कठिनाई आ रही थी। राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं में हो रही बाधा के चलते शासन ने पटवारियों के कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 7 जून से प्रभावीशील किया गया है और आगामी 3 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा।

उल्लेखनीय है कि इस एक्ट के अंतर्गत राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाएं भी आती हैं। शासन ने लोकहित में यह निर्णय लिया है। पटवारियों के हड़ताल के चलते शिक्षा सत्र चालू होने एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इन जरूरी दस्तावेजों के नहीं बनने से इन विद्यार्थियों को आने वाली दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही कृषि कार्य भी आरंभ होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांकन, बटांकन और नामांतरण की कार्यवाही शासकीय योजनाओं का लाभ लेने अत्यावश्यक है। पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में राजस्व न्यायालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है। इन सभी दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अत्यावश्यक सेवाओं की पूर्ति में बाधा होने से लोक हित प्रभावित हो रहा है और लोगों का कार्य सुचारू रूप से हो सके, उन्हें किसी तरह की दिक्कत न आये, इसके चलते यह आदेश जारी किया गया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मिडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.